

विदाई से पहले फिर सक्रिय हुआ मानसून

यूपी-बिहार समेत कई राज्यों में बारिश और आंधी का अलर्ट

नई दिल्ली,एजेंसी। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती सिस्टम बन रहा है, जिसके मंगलवार तक चक्रवाती तूफान बनने की संभावना है। बांग्लादेश ने इसका नाम 'अर्नब' रखा है। इससे पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश समेत आठ राज्यों में आंधी-बारिश होने की आशंका है।

उत्तर प्रदेश में मानसून कमजोर पड़ रहा है, लेकिन पहाड़ों पर भारी बारिश से कई नदियां उफान पर हैं। उन्नाव में सड़कों पर नाव चलानी पड़ रही है। 24



सितंबर से पश्चिमी यूपी में बारिश का अलर्ट है। 14 जिलों में अभी सामान्य

से कम बारिश हुई है। मौसम विभाग ने 24 सितंबर से

मध्य प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में अब तक मानसून की 91% बारिश हो चुकी है। वहीं, बिहार के पटना समेत 19 जिलों और छत्तीसगढ़ के 7 जिलों में बारिश का अलर्ट है। केरलम में मंगलवार को लगातार दूसरे दिन तेज बारिश की आशंका है।

राजस्थान से मानसून की विदाई शुरू हो गई है। सोमवार को राज्य में पूरे दिन मौसम साफ रहा। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर संभाग के ज्यादातर जिलों में अधिकतम तापमान 40डिग्री रहा।

बंगाल में मछुआरों ने हाथी के डूबते बच्चे को बचाया

नाव पर आते ही बचाने वाले से लिपटा

● हथिनी मां ने बच्चे को दुलारा

कोलकाता,एजेंसी। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में मछुआरों ने तेज बहाव में बह रहे हाथी के एक बच्चे की जान बचाई। गजोल्लोबा बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद हाथियों का झुंड तीस्ता नदी पार कर रहा था, तभी तेज धारा में बच्चा झुंड से अलग हो गया।

तीस्ता नदी में मछली पकड़ रहे पांच मछुआरों ने बच्चे को पानी में संघर्ष करते देखा। उन्होंने दो नावों से करीब 4 किलोमीटर तक उसका पीछा किया। इसके बाद तीन मछुआरे पानी में उठे और बच्चे को नाव पर खींचकर सुरक्षित बाहर निकाला। नाव में हाथी का बच्चा एक मछुआरे से लिपट गया। बच्चे को वन विभाग को सौंप दिया गया। उसे तुरंत इलाज दिया गया और



उसकी मां की तलाश शुरू की गई। करीब दो घंटे बाद वन विभाग, स्थानीय लोगों और मछुआरों ने बच्चे को उसकी मां से मिलाया। मां हथिनी बच्चे के पास पहुंची और उसे थपकी दी। इसके बाद उसने बच्चे को दुलारा।

: वीफ बॉक्स :

आईआईटी बॉम्बे कैपस-

हॉस्टल से सीलिंग फैन हटेंगे

सुसाइड केस के बाद फैसला

मुंबई,एजेंसी। IIT बॉम्बे में बोटिंग स्टूडेंट साहिल रविंद्र वाकोडे की मौत के बाद कैपस और हॉस्टल में लगे सीलिंग फैन हटाकर वॉल फैन लगाने का फैसला लिया गया है। कैपस में वॉल फैन पहुंचने की तस्वीर सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई है। सूत्रों के मुताबिक, पंखे बदलने पर चर्चा जुलाई में एक छात्र की मौत के बाद शुरू हुई थी। 18 सितंबर को साहिल की मौत के बाद इस फैसले को लागू किया गया। साहिल की मौत को लेकर छात्रों का प्रदर्शन पांचवें दिन भी जारी है। छात्र संस्थान में जवाबदेही, पारदर्शिता, छात्र कल्याण और मेटल हेल्थ की व्यवस्था में बदलाव की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ IIT बॉम्बे फैकल्टी फोरम ने आरोपी प्रोफेसर सूर्यनारायण दुल्ला का समर्थन किया है। वहीं IIT दिल्ली और IIT मद्रास की फैकल्टी भी प्रोफेसर के बचाव में आगे आए हैं।

क्राइम ब्रांच ने बताया 18 सितंबर को सीसीटीवी में क्या दिखा : साहिल 22 साल का था और IIT बॉम्बे के एनजी साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग में BTech सेकंड ईयर में पढ़ता था। वह महाराष्ट्र के यवतमाल जिले का रहने वाला था।

केतन हत्याकांड में पिता बोले- सिया के परिवार पर शक

चार्जशीट की कॉपी सहित 5 मांगें रखीं



पुणे,एजेंसी। पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड में उनके पिता विशाल अग्रवाल ने सोमवार को सिया गोयल के परिवार के सदस्यों के भी हत्या की साजिश में शामिल होने की आशंका जताई। उन्होंने कहा कि सिया के पिता, मां, भाई, चाचा और चाची इसमें शामिल हो सकते हैं, हालांकि वह चार्जशीट पढ़ने के बाद ही इस बारे में विस्तार से कुछ कहेंगे। विशाल ने केतन को हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों की मौत की सजा देने की मांग की है।

उन्होंने कोर्ट से चार्जशीट की कॉपी देने, मामले की सुनवाई फास्ट-ट्रैक कोर्ट में कराने और उच्च न्यायालय को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने न्याय की नियुक्ति और फास्ट-ट्रैक ट्रायल के लिए सरकार से जरूरी अधिसूचना जारी करने का अनुरोध किया है। पुणे ग्रामीण पुलिस ने शनिवार को वडगांव मावल कोर्ट में 5,053 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की।

गुम शादी की खबरों पर सवाल: सिया और उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी की सीक्रेट शादी की खबरों पर भी विशाल ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अगर दोनों की शादी पहले ही हो चुकी थी, तो सिया के परिवार ने उनके बेटे केतन से उसकी शादी कराने की कोशिश क्यों की।

धार्मिक वजह से वंदे मातरम न गाना अपराध नहीं

● सुप्रीम कोर्ट बोला: आपराधिक कार्रवाई नहीं हो ● 47 दिन पहले बने कानून पर केंद्र से जवाब मांगा

नई दिल्ली,एजेंसी। गूगल ने भारत से जुड़ी ऑनलाइन बाल यौन शोषण मामलों की जानकारी सीधे भारतीय एजेंसियों को देने पर सहमति जताई है। अब ऐसे मामलों की सूचना पहले अमेरिका की संस्था नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन को भेजने की जरूरत नहीं होगी। इससे भारतीय पुलिस को खतरे में फंसे बच्चों तक जल्दी पहुंचने में मदद मिल सकती है। गूगल के प्रवक्ता ने सोमवार को कहा कि कंपनी बाल यौन शोषण का



पता लगाने, उसे रोकने, हटाने और रिपोर्ट करने के लिए काफी निवेश करती

है। भारत ने बड़ी टेक कंपनियों को रिपोर्टिंग तेज करने को कहा था: भारत सरकार ने बड़ी टेक कंपनियों से बच्चों से जुड़ी आपत्तिजनक सामग्री की रिपोर्टिंग तेज करने को कहा था। खासकर उन मामलों में, जहां किसी बच्चे पर तत्काल खतरा हो सकता है। भारतीय अधिकारियों का कहना था कि अमेरिका स्थित संस्था के जरिए रिपोर्ट भेजने में देरी होती है। इससे खासकर उस समय परेशानी बढ़ती है, जब किसी

बच्चे को तत्काल खतरा हो और पुलिस को तुरंत कार्रवाई करनी हो। मेटा ने भी बदली रिपोर्टिंग व्यवस्था: यह फैसला मेटा की पिछले सप्ताह की घोषणा के बाद आया है। मेटा ने भी भारत में बाल यौन शोषण से जुड़े मामलों की जानकारी सीधे संबंधित भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को देने पर सहमति जताई थी। सरकारी सूत्रों ने उस समय कहा था, 'भारत में किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के संचालन के लिए बच्चों की ऑनलाइन

सुरक्षा बुनियादी सिद्धांत है। इस पर कोई समझौता नहीं होगा।' अमेरिका, यूरोपीय संघ और अन्य क्षेत्रों के अधिकारियों ने प्लेटफॉर्म से सामग्री का पता लगाने और रिपोर्टिंग तेज करने को कहा है। इसके बावजूद, ज्यादातर देशों में अमेरिकी गैर-लाभकारी संस्था ऐसी रिपोर्ट्स के लिए मुख्य सूचना केंद्र बनी हुई है। भारत की पहल का लक्ष्य सीधे रिपोर्टिंग चैनल बनाना है। इससे भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियां विदेशी मध्यस्थ

2025 में 2.13 करोड़ से ज्यादा रिपोर्ट मिलीं... बाल यौन शोषण सामग्री दुनियाभर में बढ़ती चिंता बनी हुई है। नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन की साइबरटिपलाइन को 2025 में दुनियाभर से बच्चों के संभावित यौन शोषण से जुड़ी 2.13 करोड़ से ज्यादा रिपोर्ट मिलीं।

के जरिए सूचना पहुंचने का इंतजार किए बिना कार्रवाई कर सकेंगी।

गूगल बच्चों से जुड़े यौन शोषण मामलों की जानकारी देगा

● रपोट सीधे भारत सरकार को भेजी जाएगी ● पहले अमेरिकी संस्था को दी जाती थी

नई दिल्ली,एजेंसी। गूगल ने भारत से जुड़ी ऑनलाइन बाल यौन शोषण मामलों की जानकारी सीधे भारतीय एजेंसियों को देने पर सहमति जताई है। अब ऐसे मामलों की सूचना पहले अमेरिका की संस्था नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन को भेजने की जरूरत नहीं होगी। इससे भारतीय पुलिस को खतरे में फंसे बच्चों तक जल्दी पहुंचने में मदद मिल सकती है।

गूगल के प्रवक्ता ने सोमवार को कहा कि कंपनी बाल यौन शोषण का पता लगाने, उसे रोकने, हटाने और रिपोर्ट करने के लिए काफी निवेश करती है।

भारत ने बड़ी टेक कंपनियों को रिपोर्टिंग तेज करने को कहा था: भारत सरकार ने बड़ी टेक कंपनियों से



बच्चों से जुड़ी आपत्तिजनक सामग्री की रिपोर्टिंग तेज करने को कहा था। खासकर उन मामलों में, जहां किसी बच्चे पर तत्काल खतरा हो सकता है। भारतीय अधिकारियों का कहना था कि अमेरिका स्थित संस्था के जरिए रिपोर्ट भेजने में देरी होती है। इससे खासकर उस समय परेशानी बढ़ती है, जब किसी बच्चे को तत्काल खतरा हो और पुलिस को तुरंत कार्रवाई करनी हो।

मेटा ने भी बदली रिपोर्टिंग व्यवस्था: यह फैसला मेटा की पिछले सप्ताह की घोषणा के बाद आया है। मेटा ने भी भारत में बाल यौन शोषण से जुड़े मामलों की जानकारी सीधे संबंधित भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को देने पर सहमति जताई थी। सरकारी सूत्रों ने उस समय कहा था, 'भारत में किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के संचालन के लिए बच्चों की

2025 में 2.13 करोड़ से ज्यादा रिपोर्ट मिलीं... बाल यौन शोषण सामग्री दुनियाभर में बढ़ती चिंता बनी हुई है। नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन की साइबरटिपलाइन को 2025 में दुनियाभर से बच्चों के संभावित यौन शोषण से जुड़ी 2.13 करोड़ से ज्यादा रिपोर्ट मिलीं।

ऑनलाइन सुरक्षा बुनियादी सिद्धांत है। इस पर कोई समझौता नहीं होगा।' अमेरिका, यूरोपीय संघ और अन्य क्षेत्रों के अधिकारियों ने प्लेटफॉर्म से सामग्री का पता लगाने और रिपोर्टिंग तेज करने को कहा है। इसके बावजूद, ज्यादातर देशों में अमेरिकी गैर-लाभकारी संस्था ऐसी रिपोर्ट्स के लिए मुख्य सूचना केंद्र बनी हुई है।

तेलंगाना के अस्पताल में आग, 2 नवजातों की मौत

हैदराबाद,एजेंसी। तेलंगाना के आदिलाबाद जिले के सरकारी RIMS अस्पताल की स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट (SNCU) में सोमवार रात करीब 11:50 बजे आग लग गई। हादसे में दो नवजातों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य की हालत गंभीर है।

अधिकारियों के मुताबिक, यूनिट में 27 नवजातों का इलाज चल रहा था। आग के बाद 25 बच्चों को अलग-अलग निजी अस्पतालों में शिफ्ट किया गया। शुरुआती जानकारी में एसी में खराबी के बाद विस्फोट की आशंका जताई गई है। हालांकि सही वजह जांच पूरी होने के बाद सामने आएगी।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत में इस साल अस्पतालों में आग लगने से 23 लोगों की मौत सामने आई है। इनमें ओडिशा के कटक में 12 मरीज, बिहार के मुजफ्फरपुर में 5 मरीज, महाराष्ट्र के अमरावती में 3 नवजात,

27 बच्चे एडमिट थे,एसी फटने की आशंका



तेलंगाना के आदिलाबाद में 2 नवजात और उत्तर प्रदेश के कानपुर में 1 नवजात शामिल है। 25 बच्चों को दूसरे अस्पतालों में भेजा गया: अधिकारियों के मुताबिक, आग में एक 5 दिन के बच्चे की मौत हुई। दूसरे नवजात को आग के बाद

निजी अस्पताल ले जाया गया था, जहां मंगलवार सुबह उसकी मौत हो गई। आग के बाद 25 बच्चों को इलाज के लिए अलग-अलग निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। इनमें से दो की हालत गंभीर है, जबकि बाकी बच्चों की सेहत पर लगातार नजर रखी जा रही है।

सीएम ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने को कहा... मुख्यमंत्री ए. रेवेंट रेड्डी ने नवजातों की मौत पर दुख जताया। उन्होंने इलाज करा रहे बच्चों को बेहतर और एडवांस मेडिकल केयर देने और उनकी हालत पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए। साथ ही घटना की जांच के बाद रिपोर्ट सौंपने और अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने को कहा।

योगी बोले: 6 महीने में 1 लाख सरकारी नौकरी देंगे

● सैफई सिडिकेट शिवपाल से गिनती पूछे, टीजीटी-पीजीटी अभ्यर्थियों के मुद्दे पर भी लिया संज्ञान

लखनऊ,एजेंसी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार, 22 सितंबर को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 3,567 प्रधानाचार्यों, प्रधानाध्यापकों, प्रवक्ताओं (PGT) और सहायक अध्यापकों (TGT) को नियुक्ति-पत्र सौंपा। इन सभी की नियुक्ति ऐसे निजी स्कूलों में हुई है, जिन्हें सरकार से आर्थिक सहायता मिलती है और जहां माध्यमिक स्तर तक पढ़ाई होती है।

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'आत्मनिर्भर और विकसित भारत' के संकल्प को साकार करने की दिशा में उत्तर प्रदेश का एक ऐतिहासिक कदम है।

योगी का अखिलेश पर तंज, बोले- शिवपाल जी से गिनती पूछिए: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रशांत कुमार और उनकी पूरी टीम की तारीफ की।

उन्होंने कहा कि आयोग ने जिस पारदर्शिता और समय-सीमा के अंदर भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया है, वह मिसाल है। विपक्ष पर हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री ने सरकारी नौकरियों के आकड़ों का हिसाब दिया। उन्होंने



'1 लाख और युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे'... मुख्यमंत्री ने कहा कि 9 साल पहले जिस उत्तर प्रदेश को बीमारु राज्य कहकर विद्वाना जाता था, आज वही यूपी देश की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा 'ग्रोथ इंजन' बनकर उभरा है। राज्य की अर्थव्यवस्था तीन गुना से अधिक बढ़ चुकी है।

कहा, 'लोग पूछते हैं कि कितनों को नौकरी मिली और इसका रिजल्ट क्या आया? मैं गर्व से कहता हूँ कि हमारी सरकार ने अब तक 9.5 लाख युवाओं को बिना किसी भेदभाव और रिश्ते के सरकारी नौकरी दी है।' मुख्यमंत्री ने सैफई सिडिकेट पर तंज कसते हुए कहा- मैंने उनसे कहा कि हम नौकरी दे रहे हैं। यह नियुक्ति पत्र वितरण का हमारा तीसरा कार्यक्रम है।

मिजोरम में यूसीसी लागू करने की मांग

भाजपा विधायक बोले: एक पत्नी वाला सिस्टम मिजो महिलाओं के लिए फायदेमंद

» गैर-आदिवासियों से शादी पर सुरक्षा मिलेगी

आइजोल,एजेंसी। मिजोरम के भाजपा विधायक के हाहो ने राज्य में यूसीसी लागू करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इससे गैर-आदिवासी पुरुषों से शादी करने वाली मिजो महिलाओं को ज्यादा कानूनी सुरक्षा मिलेगी। आइजोल में भाजपा कार्यालय में एक कार्यक्रम के दौरान हाहो ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि मिजोरम में गैर-आदिवासी लोगों की मौजूदगी को देखते हुए यूसीसी लागू करने के मुद्दे की जांच होनी चाहिए।



उन्होंने कहा कि यूसीसी में एक पत्नी के प्रावधान के साथ तलाक की स्थिति में संपत्ति के बंटवारे के नियम भी हैं। इससे ऐसी शर्तियों में मिजो महिलाओं और उनके बच्चों की सुरक्षा हो सकती है।

सीएम विजय ने स्कूली बच्चों के साथ नाश्ता किया

तमिलनाडु में अब व्लास 6-8 तक के स्टूडेंट्स को भी ब्रेकफास्ट

» 15.30 लाख छात्रों को फायदा

चेन्नई,एजेंसी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ए जे जयललिता ने मंगलवार को चेन्नई में विस्तारित पेरुथलैवर कामराज प्री ब्रेकफास्ट स्क्रीम लॉन्च की। उन्होंने छात्रों को नाश्ता परोसा। उनके साथ बैठकर ब्रेकफास्ट भी किया। यह कार्यक्रम चेन्नई के तिरुवन्मिथूर स्थित गांधी ग्रामम के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में शुरू किया गया। विजय ने स्कूली



बच्चों से बातचीत भी की। पहले इस योजना का लाभ कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को मिलता था। अब कक्षा 6 से 8 तक के छात्र भी इसके दायरे में आ गए हैं। इससे राज्य के 15,454 सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के करीब 15.30 लाख अतिरिक्त छात्रों को फायदा होगा। राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 में योजना के विस्तार के लिए 217.63 करोड़ रुपए अतिरिक्त मंजूर किए हैं। इसके साथ योजना का कुल

कामराज के नाम पर योजना का नाम बदला... इस योजना का नाम पहले वीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्क्रीम था। अब इसका नाम बदलकर पेरुथलैवर कामराज प्री ब्रेकफास्ट स्क्रीम कर दिया गया है।

बजट 724 करोड़ रुपए हो गया है। यह नाम तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री के कामराज के सम्मान में रखा गया है। उन्होंने स्कूली शिक्षा की पहुंच बढ़ाने और राज्य की मिड-डे मील योजनाओं को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई थी।

संक्षिप्त समाचार

राजस्थान में वायुसेना अभ्यास ‘तरंग शक्ति’ में दिखेगा भारत का एयरपावर

अमेरिका-फ्रांस समेत 40 देश लेंगे हिस्सा



जयपुर, एजेंसी। नई दिल्ली। बहुदेशीय वायुसैनिक अभ्यास ‘तरंग शक्ति’ के दूसरे संस्करण में अमेरिका व फ्रांस समेत 40 से अधिक देश हिस्सा लेंगे। इसका आयोजन राजस्थान के जोधपुर एयर फोर्स स्टेशन पर 26 सितंबर से 12 अक्टूबर तक किया जाएगा। इसमें विभिन्न देश परिवहन विमानों समेत कई तरह के हवाई साजो-सामान के साथ शामिल होंगे।अधिकारियों के मुताबिक, अमेरिका अपने पांचवी पीढ़ी के दो-तीन एफ-35 विमानों के साथ शामिल होगा। फ्रांस अपने राफेल युद्धक विमानों और संयुक्त अरब अमीरात अपने एफ-16 युद्धक विमानों के साथ हिस्सा लेगा। यह वायुसैनिक अभ्यास भारत एवं जापान के बीच हुए द्विपक्षीय हवाई युद्धभ्यास ‘वीर गाडियन’ के ठीक बाद हो रहा है, जिसका आयोजन भी जोधपुर एयरबेस ने ही किया था। भारतीय वायुसेना इस अभ्यास में अपने मुख्य विमानों को उतारेगी, जिनमें राफेल व सुखोई-30 युद्धक विमान शामिल हैं। रक्षा अधिकारियों ने बताया कि भारतीय वायुसेना के सपोर्ट प्लेटफार्म, जैसे- एयरबोर्न अली वॉर्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट, परिवहन विमान और हवा में ईंधन भरने वाले टैंकर भी इस अभ्यास में हिस्सा लेंगे। ‘तरंग शक्ति’ के पहले संस्करण का आयोजन 2024 में किया गया था

हिमाचल में फिर बन रहे बारिश के आसार



शिमला, एजेंसी। हिमाचल प्रदेश में धूप के खिलने से तापमान में हालांकि ज्यादा वृद्धि नहीं हुई है। बावजूद इसके दिन का तापमान सामान्य से दो से तीन डिग्री अधिक दर्ज किया जा रहा है। प्रदेश में 22 व 23 सितंबर को मौसम साफ रहेगा, जबकि 24 से 27 सितंबर तक एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा की संभावना है। चक्रवात के कारण उत्तराखंड में 26 व 27 सितंबर को मध्यम से भारी वर्षा की चेतावनी दी है तो इसका असर हिमाचल में भी असर दिख सकता है। इसका ज्यादा प्रभाव 28 और 29 सितंबर को बताया जा रहा है।

कुफरी में दिन के तापमान में 2.7 डिग्री की गिरावट आई है

जबकि नाहन और बिलासपुर में 1.5 डिग्री की वृद्धि दर्ज की गई है। सबसे अधिक तापमान ऊना में 0.8 डिग्री की वृद्धि के साथ 35 डिग्री दर्ज किया गया है। कल्या, धर्मशाला और मंडी में अधिकतम तापमान सामान्य से तीन डिग्री अधिक है।

न्यूनतम तापमान में वृद्धि दर्ज: प्रदेश में न्यूनतम तापमान में एक से तीन डिग्री की वृद्धि दर्ज की गई है।

बिलासपुर में 3.5 डिग्री की वृद्धि, भरमौर में तीन जबकि बाकी स्थानों पर एक से दो डिग्री तक की वृद्धि दर्ज की गई है। प्रदेश में वर्षा से बंद 53 सड़कों को खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं।

टोंक में पंचायती राज चुनाव 2026 : प्रधान

जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए आरक्षण की लॉटरी कल, गलंस कॉलेज में प्रवेश शुरू



टोंक, एजेंसी। प्रदेश में आगामी पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 की प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में टोंक जिले की पंचायती राज संस्थाओं के विभिन्न पदों के लिए आरक्षण का निर्धारण बुधवार, 23 सितंबर को सुबह 11 बजे जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित होने वाली लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। जिला प्रशासन की ओर से लॉटरी प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और निर्धारित सरकारी नियमों व प्रावधानों के तहत संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

विदाई से पहले फिर सक्रिय हुआ मानसून, यूपी-बिहार समेत कई राज्यों में बारिश और आंधी का अलर्ट



लखनऊ, पटना, देहरादून, एजेंसी। दक्षिण-पश्चिम मानसून की विदाई से ठीक पहले कई राज्यों में मानसूनी गतिविधियां एक बार फिर से पूरी तरह सक्रिय हो गई हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने देश के 24 राज्यों में बारिश की संभावना जताई है। इनमें से 18 से अधिक राज्यों में भारी बारिश, वज्रपात और तेज तूफानी हवाओं को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तटीय और पश्चिमी इलाकों में मौसम का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल सकता है, जहां गुजरात में 50 किलोमीटर प्रति घंटे और महाराष्ट्र व गोवा में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है।

उत्तर प्रदेश में मौसम का हाल: उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधियां सीमित रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक, पूर्वी उत्तर प्रदेश में अलग-अलग जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में तेज हवाओं, गरज-चमक और बिजली गिरने के साथ व्यापक बारिश की संभावना जताई गई है।

बिहार में भारी बारिश का अलर्ट: बिहार में 22 सितंबर को मौसम मिला-जुला रहेगा और कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। हालांकि 23 सितंबर से मानसूनी बारिश जोर पकड़ेगी। 24 और 25 सितंबर को राज्य के कई जिलों में मूसलाधार बारिश, गरज-चमक और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी दिल्ली में मंगलवार को मौसम मुख्य रूप से साफ रहने का अनुमान है।

मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। दिन के समय 15 से 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने 26 और 27 सितंबर को राज्य के अधिकांश हिस्सों में बहुत भारी बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है।

राजस्थान में निकलेगी धूप: राजस्थान में 22 सितंबर को मौसम मुख्यतः शुष्क रहने और अधिकांश हिस्सों में धूप खिलने की संभावना है। जयपुर और कोटा समेत ज्यादातर जिलों में अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के करीब रह सकता है।हालांकि, पूर्वी राजस्थान के कुछ सीमित इलाकों में हल्की बौछारें पड़ने का अनुमान है।

मध्य प्रदेश में फिर सक्रिय हुआ मानसून

मध्य प्रदेश के कई जिलों में 22 सितंबर से मानसून एक बार फिर पूरी तरह सक्रिय हो गया है। इसके चलते राजधानी भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर समेत कई इलाकों में तेज बारिश, बिजली गिरने और आंधी को लेकर मौसम विभाग ने येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र और गुजरात का हाल: महाराष्ट्र और गोवा में मंगलवार को भारी बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है, जहां तटीय इलाकों में 60 किमी/घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। वहीं गुजरात और सौराष्ट्र- कच्छ क्षेत्र में 50 किमी/घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और मध्यम से भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। पूर्व और दक्षिण भारत के राज्य: झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पूर्वांचल के सभी आठ राज्यों में भी अगले 24 से 48 घंटों में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी।

निकाह कबूल है पंजाब में घर छोड़कर 17 साल की युवती ने की शादी, हाईकोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत दी सुरक्षा

चंडीगढ़, एजेंसी। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मुस्लिम व्यक्तिगत कानून से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि यौवन प्राप्त कर चुका मुस्लिम लड़का या लड़की अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह कर सकता है। अदालत ने कहा कि मुस्लिम व्यक्तिगत कानून में सामान्यतः 15 वर्ष की आयु को यौवन की आयु माना जाता है, जब तक इसके विपरीत कोई प्रमाण सामने न हो। हालांकि, हाईकोर्ट ने संबंधित निकाह की वैधता पर कोई अंतिम राय नहीं दी है। मामला लुधियाना का है, जहां 17 वर्ष 8 माह की युवती ने परिवार की इच्छा के विरुद्ध 26 वर्षीय युवक से निकाह किया था। दोनों मुस्लिम हैं और उनका कहना था कि वे एक-दूसरे को कुछ समय से जानते हैं तथा आपसी सहमति से साथ रहना चाहते हैं। याचिका के अनुसार युवती के पिता इस रिश्ते के खिलाफ थे। इसके बाद युवती ने 22 अगस्त 2026 को अपना पतुक घर छोड़ दिया और उसी दिन मुस्लिम रीति-रिवाज के अनुसार युवक से निकाह कर लिया।

परिवार की धमकियों के बाद पुलिस से मांगी सुरक्षा: परिवार की ओर से विरोध और कथित धमकियों के चलते दोनों ने 30 अगस्त को पुलिस के समक्ष जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए शिकायत दी। उन्होंने अदालत से पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की और आशंका जताई कि परिवार की ओर से उन्हें नुकसान पहुंचाया जा सकता है। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मुस्लिम व्यक्तिगत कानून के प्रावधानों पर विचार किया।

पसंद से विवाह की स्वतंत्रता: अदालत ने कहा कि मुस्लिम कानून के तहत यौवन प्राप्त कर चुका लड़का या लड़की अपनी पसंद से विवाह करने के लिए स्वतंत्र है। मुस्लिम व्यक्तिगत कानून में सामान्यतः 15 वर्ष की आयु को यौवन प्राप्त करने की उम्र माना जाता है, जब तक इसके विपरीत कोई प्रमाण उपलब्ध न हो। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि वह इस स्तर पर दोनों के निकाह की वैधता पर कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं दे रही है। याचिका का उद्देश्य मुख्य रूप से जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्राप्त करना था। हाईकोर्ट ने अंततः याचिका का निपटारा करते हुए लुधियाना ग्रामीण के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया कि वह 30 अगस्त को दी गई सुरक्षा संबंधी शिकायत पर विचार करें। पुलिस को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार कानून के तहत आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।



अमेरिका में एयर ट्रेफिक सिस्टम फेल: न्यूयॉर्क के तीन बड़े एयरपोर्ट पर उड़ानें ठप; क्या है वजह

अमेरिका में एयर ट्रेफिक सिस्टम फेल, सैकड़ों उड़ानें प्रभावित



अल्बानी, एजेंसी। अमेरिका के पूर्वोत्तर हिस्से में सोमवार को एयर ट्रेफिक कंट्रोल सिस्टम में तकनीकी खराबी के कारण हवाई सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो गईं। सैकड़ों उड़ानें रद्द करनी पड़ीं और न्यूयॉर्क शहर के तीनों प्रमुख एयरपोर्ट जॉन एफ. कैनेडी (जेएफके), ला गार्डिया और नेवारक पर कई घंटों तक उड़ानों का संचालन प्रभावित रहा। फिलाडेल्फिया की उड़ानों पर भी इसका असर पड़ा। यह पेशानी ऐसे समय आई, जब संयुक्त राष्ट्र महासभा में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में विदेशी नेता न्यूयॉर्क पहुंच रहे थे। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वाशिंगटन डीसी से न्यूयॉर्क जाने वाली उड़ान तय समय पर खाना हुई।

फिलाडेल्फिया के एयर ट्रेफिक सेंटर में फेल हुआ सर्किट: अमेरिकी संघीय विमानन प्रशासन यानी एफएए के मुताबिक, फिलाडेल्फिया स्थित एक एयर ट्रेफिक कंट्रोल सुविधा में सोमवार सुबह मुख्य सर्किट फेल हो गया। इस सुविधा से फिलाडेल्फिया के अलावा न्यूयॉर्क के प्रमुख एयरपोर्ट के लिए हवाई यातायात नियंत्रित होता है। मुख्य सर्किट के फेल होने के बाद इन इलाकों में आने वाली और जाने वाली उड़ानों पर असर पड़ा।

बैकअप फाइबर लाइन भी नहीं कर पाई काम: मामला तब और गंभीर हो गया, जब एफएए को पता चला कि बैकअप फाइबर ऑप्टिक लाइन भी कट चुकी है। यह लाइन न्यू ब्रॉक्सविक और नेवारक, न्यू जर्सी के बीच कहीं निर्माण कार्य के दौरान क्षतिग्रस्त हुई थी। यानी मुख्य कनेक्शन के फेल होने के बाद जिस बैकअप व्यवस्था का इस्तेमाल किया जा सकता था, वह भी उपलब्ध नहीं थी। एफएए दोनों कनेक्शन ठीक करने में जुटा एफएए प्रशासक ब्रायन बेडफोर्ड ने बताया कि एजेंसी मुख्य लाइन पर नया सर्किट लगाने के साथ बैकअप फाइबर ऑप्टिक लाइन को भी ठीक करने में जुटी है। एफएए की कोशिश है कि एयर ट्रेफिक कंट्रोल की जरूरी कनेक्टिविटी जल्द से जल्द बहाल हो जाए। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि पूरी व्यवस्था सामान्य होने में कितना समय लगेगा।

फाइबर लाइन की मरम्मत में लग सकते हैं 13 घंटे: ब्रायन बेडफोर्ड के मुताबिक, बैकअप फाइबर लाइन को ठीक करने में करीब 13 घंटे लग सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह बड़ा नुकसान है और एफएए इसे ठीक करने के लिए काम कर रहा है। सोमवार को फेल हुआ मुख्य सर्किट पहले से ही अमेरिका की एयर ट्रेफिक कंट्रोल व्यवस्था के बड़े बदलाव के तहत बदला जाना था।

कुछ उड़ानें दोबारा शुरू, लेकिन देरी जारी रहने की आशंका: सोमवार दोपहर तक ला गार्डिया और फिलाडेल्फिया एयरपोर्ट पर कुछ उड़ानें दोबारा शुरू हो गई थीं। इसके बावजूद दिन के बाकी हिस्से में उड़ानों में काफी देरी होने की आशंका थी।

टेक्सास में 90 फुट की हनुमान प्रतिमा पर बवाल: यूट्यूबर की धमकी से गरमाई सियासत, विवाद क्यों

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका के टेक्सास में भगवान हनुमान की 90 फुट ऊंची प्रतिमा को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। शूगरलैंड स्थित अष्टलक्ष्मी मंदिर में लगी इस प्रतिमा को हटाने की मांग एक रूढ़िवादी यूट्यूबर ने की है। इसके बाद हिंदू संगठनों और कई लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया। यह विवाद ऐसे समय सामने आया है, जब टेक्सास में अमेरिकी मध्यावधि चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म है और आप्रवासी विरोधी बयानबाजी भी चर्चा में है।

अष्टलक्ष्मी मंदिर में स्थापित इस प्रतिमा को 'स्टैच्यू ऑफ द यूनिन' कहा जाता है। इसकी प्राण प्रतिष्ठा अगस्त 2024 में हुई थी। दावा किया जा रहा है कि तब से ही कुछ ईसाई रूढ़िवादी समूह इसे लेकर आपत्ति जताते रहे हैं और इसे 'अईसाई' बताते हैं। अब रूढ़िवादी यूट्यूबर जेसी ह्यूजेस की टिप्पणी के बाद यह मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है।

यूट्यूबर ने कहा- जब



जोतेंगे तो इसे गिरा देंगे: जेसी ह्यूजेस ने सोशल मीडिया पर हनुमान प्रतिमा की तस्वीर साझा की। इसके साथ उन्होंने लिखा, 'जब हम जीतेंगे, तो इसे गिरा देंगे।' उनकी इस टिप्पणी के बाद हिंदू समूहों और विचारकों ने विरोध जताया। अमेरिकी सेना के पूर्व सैनिक रुचि बख्शी ने ह्यूजेस की टिप्पणी को राष्ट्रविरोधी बताया और इसे हिंदू धर्म के खिलाफ खतरा करार दिया।

पूर्व सैनिक बोले- पूजा स्थल को निशाना बनाना गलत: रुचि बख्शी ने कहा कि किसी अमेरिकी समुदाय के पूजा स्थल को सिर्फ इसलिए नुकसान पहुंचाने की बात करना कि वहां किसी दूसरे धर्म को मानने वाले लोग पूजा करते हैं, हिंदू धर्म के खिलाफ खतरा है। उन्होंने खुद से मुखर होना इतना आवश्यक है।



को एक अमेरिकी-हिंदू बताया और अमेरिका में हिंदू विरोधी नफरत को लेकर चिंता जताई। बख्शी ने कहा कि अगर अमेरिका में जीत का मतलब हिंदू मंदिरों को गिराना है, तो ऐसा चाहने वाले उस देश की बात नहीं कर रहे जिसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी।

हिंदू संगठन और दूसरे पूर्व सैनिक भी समर्थन में आए: बख्शी के बयान को कोएलिशन ऑफ हिंदूज ऑफ नॉर्थ अमेरिका (सीओएचएनए) और टेक्सास में रहने वाले अमेरिकी सेना के पूर्व सैनिक कार्ल व्हीलेस का समर्थन मिला। व्हीलेस खुद को राजनीतिक चर्चा के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवार बो फ्रेंच ने बताया। उन्होंने लिखा था कि उन्होंने इसे, 'इस साल यूटी ग्रेजुएशन ऐसा दिख रहा था और इसके साथ कहा था कि समस्या अब जाहिर तौर पर किसी की कल्पना से कहीं ज्यादा खराब है।

जयशंकर ने की पी4एम समिट की अध्यक्षता, कहा- वैश्विक व्यवस्था दबाव में, बहुपक्षीय सहयोग जरूरी

संयुक्त राष्ट्र, एजेंसी। 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के इतर बहुपक्षवाद शिखर सम्मेलन में यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने वैश्विक चुनौतियों पर जोर दिया। भारत ने सह-प्रायोजक के रूप में बहुपक्षवाद को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र में सुधार की प्रकालत की। सम्मेलन में वैश्विक चुनौतियों से निपटने और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने इस पहल की सह-मेजबानी ऑस्ट्रेलिया, बारबाडोस, ब्राजील, कनाडा, भारत और केन्या के साथ की। उन्होंने सभी महाद्वीपों से अंतरराष्ट्रीय समुदाय के एक व्यापक और विविध प्रतिनिधित्व पर प्रसन्नता व्यक्त की। कोस्टा ने कहा कि हम सभी विभिन्न क्षेत्रों, संस्कृतियों और इतिहासों से आते हैं, फिर भी हम समान चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। विषय इस समय एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है, जहां संघर्ष लगातार फैल रहा है। अंतरराष्ट्रीय कानून का बार-बार उल्लंघन किया जा रहा है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य भी शामिल हैं। बहुपक्षीय प्रणाली



इस समय भारी तनाव में है। जलवायु परिवर्तन, महामारी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और आर्थिक असुरक्षा जैसी चुनौतियां इतनी व्यापक हैं कि कोई भी देश, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, उनका अकेले सामना नहीं कर सकता। इसलिए हमें टकराव को सहयोग में बदलना चाहिए। उन्होंने बहुपक्षीय सहयोग, आपसी सम्मान और अंतरराष्ट्रीय कानून पर आधारित एक वैश्विक नेटवर्क बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने इस पहल को शुरू करने के लिए राष्ट्रपति एंटोनियो कोस्टा को

धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, भारत सह-प्रायोजक के रूप में इस पहल में शामिल होकर प्रसन्न है। जयशंकर ने आगे कहा कि हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब वैश्विक व्यवस्था तनाव में है। पिछले कुछ दशकों से दुनिया में एक स्थिर पुनर्संतुलन देखा जा रहा है, जो एक लंबे समय से अपेक्षित संरचनात्मक विकास था। हालांकि, अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, भू-राजनीतिक तनाव और वास्तविक संघर्षों ने इसे एक अलग चरित्र दिया है। यदि इसे अनियंत्रित छोड़ दिया गया, तो यह अंतरराष्ट्रीय सहयोग की भावना पर ही सवाल उठाएगा। इसीलिए इस मोड़ पर बहुपक्षवाद का दृढ़ता से मुखर होना इतना आवश्यक है।

बहुपक्षवाद की आवश्यकता क्यों है: कोस्टा ने स्पष्ट किया कि बहुपक्षवाद के साझेदारों की यह पहल एक खुला मंच है। यह दुनिया के सभी हिस्सों के साझेदारों के लिए है जो सामान्य सिद्धांतों की रक्षा करने को तैयार हैं। इसका लक्ष्य ठोस समाधानों की दिशा में मिलकर काम करना है। यह मंच संवाद, गठबंधन निर्माण और व्यावहारिक सहयोग के लिए एक नेटवर्क के रूप में कार्य करेगा। यह हमें सामान्य चुनौतियों का सामना करने में

समन्वय स्थापित करने में मदद करेगा। हमारा मुख्य उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र और अन्य बहुपक्षीय प्रारूपों के कार्य का समर्थन करना है। हम साझा प्रतिबद्धताओं को ठोस कार्रवाई में बदलने में सहायता करेंगे। जयशंकर ने भी बहुपक्षवाद की आवश्यकता पर दृढ़ता से जोर दिया। उन्होंने कहा कि यहां दांव पर केवल शब्द या अधिव्यक्तियां नहीं हैं। बल्कि बहुत वास्तविक मुद्दे हैं जिनका समाधान आवश्यक है। शांति और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा का भविष्य, जलवायु कार्रवाई और जलवायु न्याय, उभरती प्रौद्योगिकियां और विकास वित्त, आतंकवाद का मुकाबला, आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करना, तथा आपदा लचीलापन सुनिश्चित करना और महामारियों की तैयारी करना। ये सभी सहयोग की इच्छा पर निर्भर करते हैं।

वैश्विक चुनौतियों से निपटने की प्राथमिकताएं क्या हैं: एंटोनियो कोस्टा ने इस संबंध में तीन मुख्य प्राथमिकताएं बताईं। पहली प्राथमिकता उन नियमों और संस्थाओं की रक्षा करना है जो हम सभी की सुरक्षा करते हैं। इनमें संयुक्त राष्ट्र चार्टर, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान और अंतरराष्ट्रीय कानून शामिल हैं।

जनसुनवाई में 273 आवेदकों की समस्याएं सुनीं, कलेक्टर ने त्वरित निराकरण के दिए निर्देश

गेंदलाल को व्हीलचेयर और सुनील को बैसाखी उपलब्ध कराने के निर्देश, मौके पर ही शुरू हुई कार्रवाई



मीडिया ऑडीटर, सीधी (निग्र)। जिला पंचायत सभाकक्ष में मंगलवार को आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में कलेक्टर विकास मिश्रा ने जिले के विभिन्न

क्षेत्रों से पहुंचे 273 आवेदकों की समस्याएं सुनीं उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को प्राप्त आवेदनों का शीघ्र एवं प्रभावी निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश

दिए कलेक्टर ने कहा कि नागरिकों की समस्याओं के समाधान में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए और प्रत्येक आवेदन पर की गई कार्रवाई की जानकारी आवेदक को

उपलब्ध कराई जाए कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि हितग्राहीमूलक योजनाओं से संबंधित प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण किया जाए उन्होंने कहा कि यदि किसी आवेदन का निराकरण संभव नहीं है अथवा किसी कारण से आवेदन निरस्त किया जाता है तो इसकी स्पष्ट वजह संबंधित आवेदक को बताई जाए जनसुनवाई का उद्देश्य नागरिकों की समस्याओं को सुनने के साथ उनका प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है। जनसुनवाई के दौरान ग्राम बरमबावा, जनपद पंचायत सीधी निवासी दिव्यांग गेंदलाल बर्हेलिया ने व्हीलचेयर उपलब्ध कराने की मांग रखी उन्होंने बताया कि पोलियो के कारण उन्हें चलने-फिरने में कठिनाई होती है दैनिक कार्यों के लिए भी उन्हें सहारे

की आवश्यकता पड़ती है उनकी समस्या सुनने के बाद कलेक्टर ने सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अधिकारियों को तत्काल व्हीलचेयर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए इसी तरह ग्राम छुह्री, जनपद पंचायत मझौली निवासी दिव्यांग सुनील सिंह ने आवागमन में परेशानी की जानकारी दी उन्होंने बताया कि उन्हें पूर्व में उपलब्ध कराई गई बैसाखी पुगुनी होकर टूट गई है जिसके कारण आने-जाने में काफी कठिनाई हो रही है कलेक्टर ने मामले का त्वरित निराकरण करते हुए संबंधित विभाग को नई बैसाखी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए दोनों आवेदनों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश मिलने से आवेदक संतुष्ट नजर आए जनसुनवाई के दौरान ही उनकी आवश्यकताओं के

समाधान की पहल होने से उन्हें राहत मिली। जनसुनवाई में नागरिकों को विभिन्न आवश्यक सेवाएं भी उपलब्ध कराई गई स्वास्थ्य विभाग की टीम ने निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया और नागरिकों को चिकित्सकीय परामर्श प्रदान किया इसके साथ ही आधार अपडेट की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई इससे लोगों को इन सेवाओं के लिए अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सौम्या आनंद ने भी जनसुनवाई में नागरिकों की समस्याएं सुनीं उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों से विभिन्न प्रकरणों में की गई कार्रवाई की जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

पंचायत उपचुनाव के मद्देनजर 27 सितंबर से शुष्क दिवस घोषित

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निग्र)। पंचायत उप निर्वाचन वर्ष 2026 (पूर्वांर्ध) के तहत 29 सितंबर को होने वाले मतदान एवं मतगणना को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और निर्विघ्न संपन्न कराने के उद्देश्य से कलेक्टर विकास मिश्रा ने जनपद पंचायत रामपुर नैकिन क्षेत्र में शुष्क दिवस घोषित किया है यह प्रतिबंध 27 सितंबर को दोपहर 3 बजे से मतदान समाप्ति तक प्रभावी रहेगा कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24(1) तथा वर्ष 2026-27 की आबकारी व्यवस्था की कंडिका 47.2 के प्रावधानों के तहत जनपद पंचायत रामपुर नैकिन क्षेत्र में आने वाली कम्पोजिट मदिरा दुकान बुदगौना एफ-9 एवं बुदगौना सी-8 से मदिरा का क्रय, विक्रय, परिवहन और धारण पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा प्रशासन द्वारा यह कदम पंचायत उपचुनाव की प्रक्रिया को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष

बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है शुष्क दिवस के दौरान संबंधित मदिरा दुकानों को बंद रखा जाएगा और किसी भी प्रकार से शराब की बिक्री अथवा आपूर्ति की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शुष्क दिवस की अवधि में संबंधित मदिरा दुकानों से शराब का क्रय, विक्रय, परिवहन अथवा धारण करते पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं उल्लेखनीय है कि रामपुर नैकिन जनपद पंचायत क्षेत्र में 29 सितंबर को पंचायत उप निर्वाचन के तहत मतदान होना है मतदान प्रक्रिया के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा मतदाताओं को प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए प्रशासन द्वारा आवश्यक प्रतिबंधात्मक व्यवस्थाएं की जा रही हैं।

किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए गांव-गांव बनेगी किसान संघ की समिति

भारतीय किसान संघ की बैठक में किसानों को एकजुट करने और योजनाओं का लाभ दिलाने पर जोर



मीडिया ऑडीटर, सीधी (निग्र)। भारतीय किसान संघ की ओर से किसानों की समस्याओं के समाधान, संगठन को मजबूत करने और शासन की कृषि योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचाने के उद्देश्य से कृषि विज्ञान केंद्र सीधी में आवश्यक बैठक आयोजित की गई बैठक में किसानों को जिला स्तर के साथ-साथ तहसील और गांव स्तर पर संगठित कर किसान संघ की

समितियां गठित करने पर जोर दिया गया भारतीय किसान संघ के क्षेत्रीय संगठन मंत्री महेश चौधरी ने कहा कि किसानों की समस्याओं का प्रभावी समाधान तभी संभव है जब किसान एकजुट होकर अपनी समस्याओं को सामने रखें उन्होंने कहा कि संगठन का उद्देश्य किसानों को साथ लेकर उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास करना है किसानों को शासन की विभिन्न

योजनाओं की जानकारी देकर उनका लाभ दिलाने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा महाकौशल प्रांत के संगठन मंत्री तुला राम और संभागीय उपाध्यक्ष रघुवीर शरण पटेल के मार्गदर्शन में हुई बैठक में जिले के किसानों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। खाद-बीज की उपलब्धता, कृषि संबंधी सलाह, प्राकृतिक खेती और शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन सहित कई विषयों पर विचार-विमर्श हुआ किसानों को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए संगठन और प्रशासन के बीच समन्वय पर भी जोर दिया गया। कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि प्रमुख वैज्ञानिक डॉ. शैलेन्द्र सिंह गौतम ने किसानों को खेती की आधुनिक एवं प्राकृतिक पद्धतियों के संबंध में जानकारी दी उन्होंने कहा कि खेत में अलग-अलग किस्म की

फसलों को जैविक खाद के उपयोग के साथ उगाने से बेहतर पैदावार प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने प्राकृतिक खेती के कार्यक्रमों को अपनाने पर भी विशेष जोर दिया उन्होंने किसानों से कहा कि मिट्टी परीक्षण अथवा कृषि संबंधी किसी प्रकार की सलाह की आवश्यकता होने पर वे सीधे कृषि वैज्ञानिकों से संपर्क कर सकते हैं। उप संचालक कृषि आरएस गुप्ता ने कहा कि जिले के प्रत्येक तहसील और गांव में किसानों को उचित सलाह एवं सहयोग उपलब्ध कराने के लिए विस्तार अधिकारियों की तैनाती की गई है किसान इन अधिकारियों की सेवाओं का लाभ लेकर खेती की उत्पादकता बढ़ सकते हैं उन्होंने कहा कि किसानों की मांग के अनुसार समय पर खाद और बीज उपलब्ध कराने के लिए विभाग तत्पर है।

खो-खो प्रतियोगिता में पिकअप से भेजे स्कूली बच्चे, VIDEO सामने आने पर उठे सवाल

मीडिया ऑडीटर, सिंगौली (निग्र)। चित्तौरी विकासखंड के बगैया शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्रों को खो-खो प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए मालवाहक पिकअप वाहन से भेजे जाने का मामला सामने आया है मंगलवार को पिकअप में बच्चों को ले जाने का वीडियो सामने आने के बाद उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे मामला सोमवार का बताया जा रहा है जब छात्रों को प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए चित्तौरी मुख्यालय पहुंचना था। जानकारी के अनुसार स्कूल प्रबंधन ने छात्रों को प्रतियोगिता स्थल तक पहुंचाने के लिए पहले से बोलेरो वाहन की व्यवस्था की थी जिला शिक्षा अधिकारी कविता त्रिपाठी के अनुसार बच्चों को ले जा रहा बोलेरो वाहन रास्ते में खरब हो गया इसके बाद स्कूल के प्रचार्य ने अपने स्तर पर



कैल्पिक वाहन की व्यवस्था की और बच्चों को प्रतियोगिता में भेजा डीईओ ने बताया कि चित्तौरी क्षेत्र में तत्काल दूसरा वाहन उपलब्ध करना आसान नहीं था ऐसी स्थिति में प्रचार्य ने जो वाहन उपलब्ध हो सका, उसकी व्यवस्था की हालांकि पिकअप वाहन में बच्चों को बैठकर ले जाने का वीडियो सामने आने के बाद अब इस व्यवस्था को लेकर विभाग के स्तर पर भी चर्चा की जा रही है। शिक्षा विभाग के अनुसार, बच्चों को प्रतियोगिता से वाँचत न रखने के उद्देश्य से तत्काल

कैल्पिक व्यवस्था की गई थी विभाग का कहना है कि यदि बच्चों को प्रतियोगिता में नहीं भेजा जाता तो भी सवाल उठ सकते थे पैदल भेजने की स्थिति में भी आपत्ति सामने आ सकती थी मामले में बच्चों की सुरक्षा को लेकर उठे सवालों के बीच विभाग ने अपना पक्ष रखा है डीईओ ने कहा कि शिक्षा विभाग जिले में कई स्तरों पर बेहतर कार्य कर रहा है लेकिन इस तरह की एक तस्वीर सामने आने से विभाग के कामकाज को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन निर्धारित अस्थाई कुण्ड में ही करें

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निग्र)। नगर पालिका परिषद सीधी ने गणेश महोत्सव के अवसर पर नगरवासियों को शुभकामनाएं देते हुए सभी के सुख, समृद्धि, शांति एवं खुशहाली की कामना की है नगर पालिका ने नागरिकों और गणेश उत्सव समितियों से अपील की है कि गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन नदी, नालों, तालाबों अथवा अन्य प्राकृतिक जलस्रोतों में न करें नगर पालिका परिषद ने कहा कि जलस्रोतों को प्रदूषण से बचना तथा नगर की स्वच्छता एवं पर्यावरण की सुरक्षा सभी नागरिकों की सामूहिक जिम्मेदारी है। इसी उद्देश्य से प्रतिमा विसर्जन के लिए एक्सर्लेंस स्कूल मैदान में अस्थाई विसर्जन कुण्ड तैयार कराया गया है। नगरवासियों और गणेश उत्सव समितियों से अनुरोध किया गया है कि छोटी-बड़ी सभी गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन निर्धारित अस्थाई विसर्जन कुण्ड में ही किया जाए इससे प्राकृतिक जलस्रोतों को प्रदूषण से बचाने के साथ नगर की स्वच्छता व्यवस्था को भी बनाए रखने में मदद मिलेगी नगर पालिका ने प्रतिमा विसर्जन के दौरान पूजा सामग्री, फूल-माला, कपड़े, प्लास्टिक और अन्य सामग्री को नदी, तालाब अथवा नालों में नहीं डालने की अपील की है इन सामग्रियों का निर्धारित स्थल पर ही उचित निस्तारण करने को कहा गया है। नगर पालिका परिषद ने नागरिकों से गणेश महोत्सव की श्रद्धा, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के साथ मनाने में सहयोग करने का आग्रह किया है परिषद ने कहा कि धार्मिक आस्था के साथ पर्यावरण संरक्षण का ध्यान रखकर उत्सव मनाने से नगर की स्वच्छता और जलस्रोतों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है।

कलेक्टर ने गौशाला का किया निरीक्षण, पानी-बिजली की व्यवस्था सुधारने के निर्देश



मीडिया ऑडीटर, सिंगौली (निग्र)। नगर निगम क्षेत्र के देवर स्थित गौशाला का कलेक्टर ने मंगलवार को निरीक्षण किया इस दौरान उन्होंने गौशाला में पशुओं के लिए उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया और सामने आई कमियों को तत्काल दूर करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। कलेक्टर ने पशुओं के लिए पर्याप्त पानी, बिजली, सुरक्षा और अन्य जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने

दिए साथ ही हैंडपंप से पानी की नोंद तक पहुंचाने के लिए छोटी मोटर और पाइपलाइन लगाने को कहा। टूटी हुई फेंसिंग को मरम्मत कराने तथा प्रवेश द्वार पर आवश्यक गेट लगाने के निर्देश भी दिए गए।

जनभागीदारी से बेहतर होगा संचालन: गौशाला के संचालन में जनभागीदारी बढ़ाने पर भी जोर दिया गया कलेक्टर ने गौसेवा संस्थान के प्रतिनिधियों को नगर निगम के साथ नॉन-प्रॉफिट आधार पर एमओयू करने के निर्देश दिए संस्थान गौशाला की देखरेख एवं संचालन में सहयोग करेगा और रोजाना सामने आने वाली समस्याओं की जानकारी नगर निगम तथा जिला प्रशासन को देगा वर्तमान में गौशाला में नगर निगम के तीन कर्मचारी कार्यरत हैं।

छह फरार आरोपियों की गिरफ्तारी पर 11 हजार रुपये का इनाम घोषित

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निग्र)। पुलिस अधीक्षक संतोष कोरी ने जिले में फरार चल रहे छह आरोपियों की गिरफ्तारी पर कुल 11 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है। इसके अलावा शिवमूरत उपाध्याय उर्फ सुदामा पिता रोहिणी प्रसाद उपाध्याय, निवासी नरगी, थाना मड़वास तथा अनिकेत पाण्डेय पिता आशुतोष पाण्डेय, निवासी शंकरपुर/रघुनाथपुर, थाना रामपुर नैकिन की गिरफ्तारी पर 1-1 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कोई भी व्यक्ति यदि फरार आरोपियों के संबंध में ऐसी सूचना देता है, जिसके आधार पर आरोपी की गिरफ्तारी संभव हो सके अथवा आरोपी को गिरफ्तार करने में सहयोग करता है तो उसे निर्धारित इनाम राशि प्रदान की जाएगी।

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निग्र)। शासकीय कन्या महाविद्यालय, सीधी में सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत मंगलवार को मेरे सपनों का भारत विषय पर चित्रकला एवं भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया कार्यक्रम महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. ओपी नामदेव की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। सेवा संकल्प अभियान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक संचालित किया जा रहा है प्रतियोगिता का उद्देश्य छात्राओं में राष्ट्र के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के साथ रचनात्मक चिंतन, अभिव्यक्ति कौशल और सामाजिक सरोकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना रहा दोनों प्रतियोगिताओं में छात्राओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की और अपने विचारों तथा



कल्पनाओं को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। चित्रकला प्रतियोगिता में छात्राओं ने रंगों और चित्रों के माध्यम से विकसित, समृद्ध, स्वच्छ,

सशक्त एवं आत्मनिर्भर भारत की कल्पना को प्रस्तुत किया। छात्राओं ने अपनी सृजनात्मक प्रतिभा के जरिए राष्ट्र के विकास और भविष्य की

संभावनाओं को चित्रों में उकेरा चित्रकला प्रतियोगिता में अंकिता सिंह सेन ने प्रथम, अंजली यादव ने द्वितीय तथा दिव्या प्रजापति ने तृतीय स्थान

प्राप्त किया। भाषण में राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका पर चर्चा: भाषण प्रतियोगिता में छात्राओं ने मेरे सपनों का भारत विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। वक्ताओं ने देश के वर्तमान स्वरूप, भविष्य की संभावनाओं और राष्ट्र निर्माण में युवा पीढ़ी की भूमिका पर चर्चा डाला। भाषणों में शिक्षा, समान अवसर, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक समरसता और समावेशी विकास जैसे विषय प्रमुखता से सामने आए भाषण प्रतियोगिता में प्रीति जायसवाल ने प्रथम, अंजलि तिवारी ने द्वितीय तथा प्रिया मिश्रा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। रचनात्मक गतिविधियों से बढ़ती है आत्मविश्वास: महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. ओपी नामदेव ने छात्राओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि

रचनात्मक एवं बौद्धिक गतिविधियां छात्राओं के व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं ऐसी गतिविधियों से आत्मविश्वास और अभिव्यक्ति कौशल मजबूत होता है उन्होंने छात्राओं से सकारात्मक सोच और रचनात्मक ऊर्जा के साथ राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में निर्णायक मंडल के रूप में डॉ. देवेन्द्र कुमार सोनी, डॉ. अमृता ब्राह्मणे, डॉ. प्रतिमा कौल, डॉ. दीप्ति सिंह, डॉ. आका सिंह तिवारी, प्रो. गरिमा शुक्ला एवं डॉ. उमेश कुमार पाठक उपस्थित रहे कार्यक्रम का संयोजन आकांशा खादीकर ने किया चित्रकला प्रतियोगिता की प्रभारी डॉ. मनीषा सिंह तथा भाषण प्रतियोगिता की प्रभारी प्रो. रितु मिश्रा रही।

साइबर अपराधी फर्जी सिम, म्यूल खातों का करते उपयोग

साइबर धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए दूरसंचार विभाग ने यह जो चेतावनी जारी की कि सिम कार्ड के दुरुपयोग पर तीन साल की जेल और 50 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, उससे ऐसा होना बंद होगा, इसमें संदेह है। संदेह का कारण यह है कि दूसरों के दस्तावेज से सिम कार्ड लेने-देने का काम साइबर अपराधी या फिर उनसे मिले हुए सिम कार्ड बेचने वाले करते हैं। यह ध्यान रहे कि दूरसंचार विभाग को उक्त चेतावनी इसलिए जारी

करनी पड़ी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में एक प्लांट आफ सेल एजेंट ने कुछ नागरिकों के पहचान पत्रों के जरिये 25 सिम कार्ड एक्टिवेट कर दिए। इस बारे में इन नागरिकों को कोई जानकारी नहीं थी और न ही उनसे कोई सहमति ली गई थी। स्पष्ट है कि प्लांट आफ सेल एजेंट ने इन नागरिकों के पहचान पत्र छल-छय से हासिल कर रखे होंगे। चूंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इसलिए दूरसंचार विभाग को केवल चेतावनी जारी करने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए।

साइबर धोखाखड़ी और मोबाइल से जुड़ी अन्य गैर-कानूनी गतिविधियां जिस तरह बढ़ती चली जा रही हैं, उन्हें देखते हुए दूरसंचार विभाग को ऐसी व्यवस्था बनानी होगी, जिससे कोई दूसरे के नाम पर सिम कार्ड ले ही न सके। सिम कार्ड बिक्री के नियम-कानूनों को सख्त करने की आवश्यकता इसलिए और बढ़ गई है, क्योंकि साइबर फ्राड के

ज्यादातर मामलों में यही सामने आता है कि लोगों को ठगने के लिए फर्जी सिम कार्ड का इस्तेमाल हुआ। इसी तरह यह भी किसी से छिपा नहीं कि साइबर धोखाधड़ी, जो एक तरह की डकैती में बदल गई है, में म्यूल खातों का उपयोग हो रहा है। स्पष्ट है कि बैंकों को भी कमर कसने की जरूरत है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि साइबर

धोखाधड़ी के कुछ मामलों में बैंक कर्मियों की मिलीभगत पाई गई है और कुछ बैंक कर्मों पकड़े भी गए हैं। सरकार को इसका आभास होना चाहिए कि पुलिस एवं सुरक्षा एजेंसियां डाल-डाल हैं तो साइबर ठग पात-पात। साइबर ठग सुरक्षा एजेंसियों की आंखों में धूल झोंकने में इसलिए समर्थ हैं, क्योंकि वे डिजिटल तंत्र की कमजोरियों का लाभ उठाने में समर्थ हैं। एक ऐसे समय जब मोबाइल कनेक्टिविटी और डिजिटल सेवाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है, तब यह

देखा ही जाना चाहिए कि डिजिटल तंत्र में ऐसी कोन सी कमजोरियां हैं, जिनका लाभ साइबर अपराधी उठा रहे हैं। इन कमजोरियों के कारण ही वे न केवल लोगों को ठगने, बल्कि उनका पैसा विदेश भेजने में समर्थ रहते हैं। विडंबना यह है कि अधिकांश मामलों में ठगी की राशि वापस नहीं मिल पाती। सरकार को इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि साइबर ठगी के बढ़ते मामलों के बाद भी लोग उसके प्रति जागरूक क्यों नहीं हो पा रहे हैं।

भारत में डेंगू वैक्सीन की दस्तक: बीमारी के खिलाफ नई उम्मीद

चौरस वर्षेण्य

भारत में डेंगू लंबे समय से एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बना हुआ है। हर वर्ष देश के अलग-अलग हिस्सों में डेंगू के मामले सामने आते हैं और कई लोगों की जान भी चली जाती है। बदलते मौसम, शहरीकरण, जलभराव और मच्छरों के प्रजनन के अनुकूल परिस्थितियों के कारण डेंगू का दायरा लगातार चिंता का विषय बना हुआ है। वहीं इसका आतंक बड़े बड़े शहरों में अधिक है, ऐसे समय में डेंगू के खिलाफ वैक्सीन का भारत में उपलब्ध होने की खबर निश्चित रूप से उम्मीद जगाती है। यदि सब कुछ तय प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ता है तो देश में पहली डेंगू वैक्सीन के रूप में टेकेडा फार्मास्यूटिकल्स की क्यूडेंगा आने वाले वर्षों में लोगों के लिए उपलब्ध हो सकती है।

जापानी कंपनी टेकेडा फार्मास्यूटिकल्स और हैदराबाद स्थित डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज के बीच हुआ समझौता इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। समझौते के तहत डॉ. रेड्डीज भारत के निजी बाजार में टेकेडा की क्यूडेंगा वैक्सीन के प्रोमोशन और वितरण की जिम्मेदारी निभाएगी। कंपनियों के अनुसार, वैक्सीन को 2027 की पहली छमाही में भारत में लॉन्च किए जाने की संभावना है। हालांकि, इसके लिए आवश्यक स्थानीय नियामकीय और व्यावसायिक प्रक्रियाओं को पूरा करना अभी बाकी है। डेंगू के खिलाफ वैक्सीन का भारत में प्रवेश इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अब तक इस बीमारी से बचाव का मुख्य आधार मच्छरों की रोकथाम, साफ-सफाई और संक्रमित व्यक्ति को समय पर चिकित्सकीय देखभाल ही रहा है। डेंगू के लिए कोई ऐसी व्यापक रूप से उपलब्ध दवा नहीं है जो संक्रमण को सीधे खत्म कर सके। ऐसे में रोकथाम के लिए वैक्सीन की उपलब्धता सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था में एक नया विकल्प जोड़ सकती है।

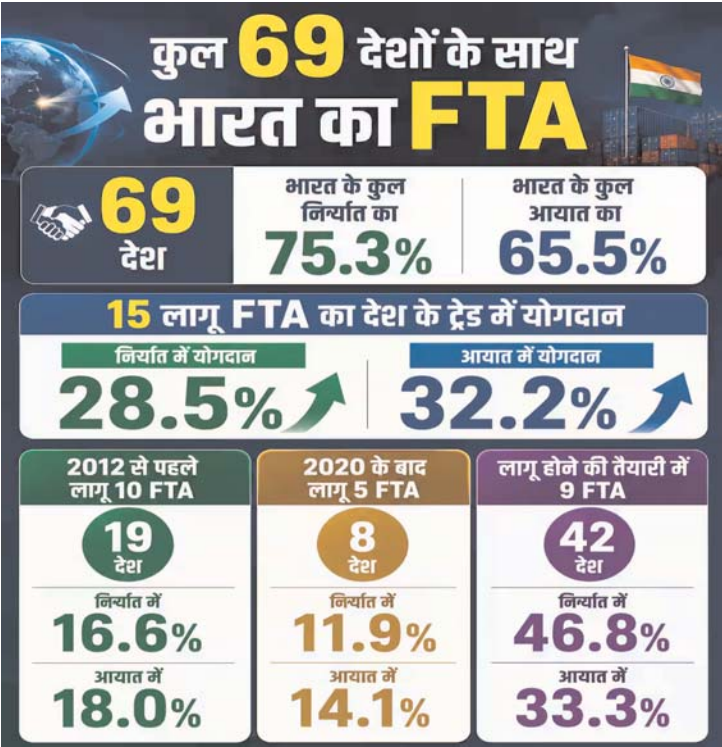
हालांकि, किसी भी नई वैक्सीन को लेकर उत्साह के साथ-साथ कुछ बुनियादी सवालों पर गंभीरता से विचार करना भी जरूरी है। सबसे पहला सवाल इसकी कीमत का है। फिलहाल क्यूडेंगा की भारत में कीमत को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। टेकेडा के इंटरकॉन्टिनेंटल मार्केट्स के प्रमुख महेंद्र नायक के अनुसार, भारत में मार्केटिंग ऑप्शरइजेशन की मंजूरी मिलने के बाद अभी स्थानीय प्रक्रियाओं को पूरा करना प्राथमिकता है। इन प्रक्रियाओं के पूरा होने से पहले वैक्सीन की कीमत का अनुमान लगाना जटिलबाजी होगी।

कीमत का सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि डेंगू केवल महानगरों या संपन्न वर्ग की समस्या नहीं है। इसका प्रभाव छोटे शहरों, कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों तक दिखाई देता है। यदि वैक्सीन निजी बाजार में आती है और इसकी कीमत आम परिवारों की पहुंच से बाहर रहती है, तो इसका लाभ सीमित आबादी तक ही सिमट सकता है। इसलिए वैक्सीन की उपलब्धता जितनी महत्वपूर्ण है, उतनी ही महत्वपूर्ण उसकी सामर्थ्य भी है। यहां सरकार की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है। कंपनियों ने संकेत दिया है कि क्यूडेंगा को भारत के सार्वजनिक टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल करना एक दीर्घकालिक लक्ष्य है। निजी बाजार में वैक्सीन की उपलब्धता शुरुआती चरण हो सकती है, लेकिन व्यापक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रभाव तभी संभव होगा जब जरूरत और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर इसे सरकारी टीकाकरण व्यवस्था में शामिल करने पर विचार किया जाए। किसी वैक्सीन को सार्वजनिक कार्यक्रम का हिस्सा बनाने की निर्णय केवल उसकी उपलब्धता के आधार पर नहीं होती। इसके लिए बीमारी का बोझ, वैक्सीन की प्रभावशीलता, सुरक्षा, अलग-अलग आयु समूहों में उसका प्रदर्शन, लागत-प्रभावशीलता और स्वास्थ्य व्यवस्था पर संभावित प्रभाव जैसे अनेक पहलुओं का मूल्यांकन आवश्यक होता है। भारत जैसे विशाल और विविध आबादी वाले देश में यह प्रक्रिया और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। क्यूडेंगा की भारत में उपलब्धता का एक दूसरा महत्वपूर्ण पहलु जागरूकता से जुड़ा है। डेंगू को लेकर समाज में अभी भी कई भ्रांतियां मौजूद हैं। कई बार लोग बुखार को सामान्य वायरल संक्रमण समझकर इलाज में देरी करते हैं। वहीं कुछ लोग डेंगू की रोकथाम को केवल मच्छर भगाने तक सीमित मानते हैं। वास्तव में डेंगू नियंत्रण के लिए व्यक्तिगत सावधानी, मच्छर नियंत्रण, स्वच्छता, समय पर जांच और चिकित्सकीय सलाह—सभी की जरूरत होती है। वैक्सीन के आने के साथ यह सुनिश्चित करना भी जरूरी होगा कि लोग इसे डेंगू से बचाव की एक अतिरिक्त रणनीति के रूप में समझें, न कि अन्य सावधानियों के विकल्प के रूप में।

किशन सनमुखदास भावनानी

मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोदिया महाराष्ट्र बताना चाहूंगा कि इन समझौतों का सकारात्मक प्रभाव भारतीय निर्यातकों को बड़े विदेशी बाजारों में कम शुल्क के साथ प्रवेश, निवेश के नए अवसर,आपूर्ति शृंखलाओं में विविधता, रोजगार तथा भारतीय विनिर्माण और सेवाओं की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ने के रूप में सामने आया है।भारत -ऑस्ट्रेलिया समझौते के बाद वस्त्र, औषधि रसायन और कृषि सहित कई क्षेत्रों में लाभ दर्ज हुआ है।वर्तमान वैश्विक व्यवस्था में जब संरक्षणवाद, शुल्क वृद्धि,आपूर्ति शृंखला का पुनर्गठन और भू- राजनीतिक तनाव अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित कर रहे हैं, तब एफटीए भारत को अनेक बाजारों से जोड़कर जोखिमों को फैलाने और निर्यात के लिए वैकल्पिक रास्ते बनाने में मदद कर सकते हैं।लेकिन इन्हें स्वतः लाभ का सौदा मानना भी उचित नहीं होगा,क्योंकि आयात बढ़ने, घरेलू उद्योग पर प्रतिस्पर्धात्मक दबाव, सीमा शुल्क राजस्व में कमी और व्यापार घाटे जैसी चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं।इसलिए भारत के लिए एफटीए की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि बाजार पहुंच का लाभ वास्तविक निर्यात, निवेश, उत्पादन, रोजगार और तकनीकी क्षमता में कितना बदलता है।

साथियों बात अगर हम भारत -न्यूजीलैंड 20 अक्टूबर 2026 से लागू होने वाला समझौते एफटीए की करें तो 27 अप्रैल 2026 को हस्ताक्षरित यह समझौता 20 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होने वाला है।न्यूजीलैंड की संसद ने 16 सितंबर को इसे लागू करने के लिए आवश्यक विधायी प्रक्रिया पूरी करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया,जिसके बाद समझौते के प्रभावी होने का रास्ता और स्पष्ट हुआ।मुम्तब व्यापार समझौता मूलतः ऐसा व्यापारिक प्रबंध है,जिसके अंगतंग दो देश एक-दूसरे के उत्पादों पर लगने वाले सीमा शुल्क को कम या समाप्त करते हैं और वस्तुओं, सेवाओं, निवेश तथा पेशेवरों की आवाजाही के लिए बाजार तक पहुंच आसान बनाते हैं।भारत के लिए इसका महत्व केवल निर्यात बढ़ाने तक सीमित नहीं है,बल्कि यह भारतीय उद्योग, छोटे कारोबार, किसानों, रोजगार, निवेश, तकनीक और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रतिष्ठा को प्रभावित करने वाला व्यापक समझौता है। भारत सरकार के अनुसार, न्यूजीलैंड भारत से आने वाले सभी उत्पादों को शुल्क-मुक्त बाजार पहुंच देगा, जबकि भारत न्यूजीलैंड के लगभग 95 प्रतिशत द्विपक्षीय व्यापार मूल्य को



समेटने वाले उत्पादों पर शुल्क में कमी अथवा समाप्ति की व्यवस्था कर रहा है। साथियों, इस समझौते की सबसे बड़ी विशेषता भारतीय निर्यातकों के लिए न्यूजीलैंड के बाजार का लगभग पूरी तरह खुलना है कपड़ा, परिधान, चमड़ा, जूते, इंजीनैरी सामान, औषधि, रसायन, प्रसंस्कृत खाद्य और श्रम-प्रधान उद्योगों को इससे नए अवसर मिल सकते हैं।सीमा शुल्क समाप्त होने में पहुंच लागत कम हो सकती है और उनकी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ सकती है।विशेष रूप से छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि बड़े उद्योगों की तुलना में छोटे निर्यातकों के लिए शुल्क और परिवहन लागत का प्रभाव अधिक होता है। सरकार ने भी इस समझौते में छोटे और मध्यम उद्यमों तथा महिला उद्यमियों को विशेष महत्व दिए जाने की बात कही है। यदि भारतीय कंपनियां गुणवत्ता, समय पर आपूर्ति और अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करने में सफल रहती हैं, तो न्यूजीलैंड का बाजार उनके लिए केवल वर्तमान निर्यात बढ़ाने का माध्यम नहीं, बल्कि आगे दूसरे विकसित बाजारों में प्रवेश की प्रतिष्ठा और अनुभव हासिल करने का मंच भी बन सकता है।

साथियों, कृषि क्षेत्र में भी समझौते का स्वल्प संतुलित रखने की कोशिश दिखाई देती है।भारत ने न्यूजीलैंड के बाजार को व्यापक रूप से खोलने के बदले अपने संवेदनशील क्षेत्रों को संरक्षण दिया है।दूध,क्रीम,पनीर, दही और अन्य प्रमुख

दुग्ध उत्पादों के साथ कई संवेदनशील कृषि वस्तुओं को शुल्क रियायतों से बाहर रखा गया है।प्याज, चीनी मसाले,खाद्य तेल और कुछ अन्य संवेदनशील वस्तुओं पर भी संरक्षण बनाए रखा गया है।दूसरी ओर, लकड़ी ऊन,भेड़ के मांस और कच्ची खाद्य जैसे उत्पादों पर शुल्क समाप्त करने अथवा घटाने की व्यवस्था की गई है, जिससे भारतीय अवसर मिल सकते हैं।सीमा शुल्क समाप्त होने में पहुंच लागत कम हो सकती है और उनकी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ सकती है।

साथियों, इस समझौते का दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ निवेश है। न्यूजीलैंड ने अगले 15 वर्षों में भारत में 20 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है।यदि यह निवेश वास्तविक परियोग नाओं में परिवर्तित होता है तो विनिर्माण,आधारभूत ढांचे, नवाचार,कृषि उत्पादकता, आधुनिक तकनीक और रोजगार के क्षेत्र में इसके प्रभाव दिखाई दे सकते हैं।समझौते में कौशल और पेशेवरों की आवाजाही को भी महत्व दिया गया है।पांच हजार तक कुशल भारतीयों के लिए अस्थायी रोजगार मार्ग, युवाओं के लिए कार्य-अवकाश व्यवस्था तथा विद्यार्थियों और कुशल स्नातकों के लिए अध्ययन के बाद काम के अवसर भारतीय प्रतिभाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय अनुभव के नए रास्ते खोल सकते हैं।स्वास्थ्य, पारंपरिक चिकित्सा,

योग, शिक्षा, पर्यटन और खेल जैसे क्षेत्रों में सहयोग भी भारत की सेवाक्षेत्रीय क्षमता को बढ़ाने में सटिका से सहायक हो सकता है। साथियों, इसका प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर कई स्तरों पर पड़ सकता है।निर्यात बढ़ने से विदेशी मुद्रा आय बढ़ सकती है,उत्पादन का विस्तार हो सकता है और श्रम-प्रधान उद्योगों में रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं।यदि न्यूजीलैंड से आने वाला निवेश उत्पादन क्षमता और आधारभूत ढांचे में लगता है तो घरेलू आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिल सकती है। छोटे और मध्यम उद्यमों का विदेशी खरीदारों तक सीधी पहुंच मिलने से उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों को अपनाने की प्रेरणा मिल सकती है। साथ ही भारतीय किसानों के लिए सेब, कीवी और मनुका शहद जैसे क्षेत्रों में उत्पादकता सहयोग तथा तकनीकी ज्ञान के अवसर भी सटिका से समझौते का हिस्सा हैं।

साथियों शेयर बाजार पर इसका प्रभाव प्रत्यक्ष से अधिक क्षेत्र-विशेष के माध्यम से दिखाई दे सकता है।जिन भारतीय कंपनियों का न्यूजीलैंड में निर्यात बढ़ सकता है, उनके लिए लागत घटने और बाजार विस्तार की संभावना सकारात्मक मानी जा सकती है। कपड़ा, चमड़ा, जूते,इंजीनियरी,औषधि, प्रसंस्कृत खाद्य और कुछ सेवा क्षेत्रों की कंपनियां नए अवसरों की तलाश कर सकती हैं। हालांकि शेयर बाजार केवल किसी एक समझौते से संचालित नहीं होता। ब्याज दरें,वैश्विक मांग, कच्चे तेल की कीमत, मुद्रा विनिमय दर,विदेशी निवेश और व्यापक भू-राजनीतिक परिस्थितियां भी बाजार को प्रभावित करती हैं। इसलिए इस समझौते को बाजार में तत्काल और सार्वभौमिक तेजी की गारंटी मानना उचित नहीं होगा। इसका वास्तविक प्रभाव कंपनियों के निर्यात आंकड़ों, लाभ, नए आदेशों और सटीकता से निवेश के वास्तविक प्रवाह में दिखाई देगा। साथियों भारत की अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से भी यह समझौता महत्वपूर्ण है।भारत अब केवल बड़ा उपभोक्ता बाजार नहीं, बल्कि विश्वसनीय उत्पादन और निर्यात साझेदार के रूप में अपनी पहचान मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। न्यूजीलैंड जैसे विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश के साथ व्यापक व्यापारिक समझौता भारत की आर्थिक कूटनीति की बढ़ती सक्रियता को दर्शाता है। भारत हाल के वर्षों में अनेक व्यापारिक साझेदारों के साथ समझौतों को आगे बढ़ा रहा है। सरकारी अभिलेखों के अनुसार भारत ने 16 मुक्त व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं; हालांकि नए समझौतों में से कुछ 20 सितंबर

2026 तक अभी लागू होने की अंतिम कानूनी प्रक्रिया में थे। इसलिए केवल सख्या बताकर सभी को सक्रिय समझौते कहना तथ्यात्मक रूप से उचित नहीं होगा।इसी व्यापक व्यापार कूटनीति में कनाडा के साथ महत्वपूर्ण है। भारत और कनाडा के बीच अगले दौर का व्यापार वार्ता 5 अक्टूबर 2026 से शुरू होने वाली है। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया को गति मिलने की संभावना है। इसका अर्थ है कि भारत एक साथ अनेक विकसित और उभरते बाजारों में अपनी व्यापारिक पहुंच बढ़ाने की सटीकता से कोशिश कर रहा है।

साथियों फिर भी मुक्त व्यापार समझौते को केवल लाभ का दस्तावेज मानना उचित नहीं होगा। सीमा शुल्क कम होने से सरकारी राजस्व पर प्रभाव पड़ सकता है, आयात बढ़ने पर कुछ घरेलू उद्योगों पर प्रतिस्पर्धात्मक दबाव आ सकता है और यदि निर्यात की तुलना में आयात अधिक तेजी से बढ़े तो व्यापार घाटे की चुनौती सामने आ सकती है। इसके अलावा निर्यातकों को मूल-स्थान संबंधी नियम, गुणवत्ता मानक, प्रमाणन और विदेशी बाजार की नियामकीय आवश्यकताओं का पालन करना होगा। केवल शुल्क समाप्त हो जाने से निर्यात अपने आप नहीं बढ़ता; उत्पादन की गुणवत्ता, कीमत, आपूर्ति की विश्वसनीयता और वैश्विक मांग भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पायेंगे कि भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते की असली परीक्षा 20 अक्टूबर 2026 को इसके लागू होने के बाद शुरू होगी। समझौते ने भारतीय उत्पादों के लिए न्यूजीलैंड का बाजार खोला है, निवेश के नए रास्ते बनाए हैं और पेशेवरों तथाविद्यार्थियों के लिए अवसर बढ़ाए हैं।साथ ही भारत ने डेयरी और संवेदनशील कृषि क्षेत्रों में सुरक्षा बनाएरखकर घरेलू हितों को भी महत्व दिया है।भारत अब केवल बड़ा उपभोक्ता बाजार नहीं, बल्कि विश्वसनीय उत्पादन और निर्यात साझेदार के रूप में अपनी पहचान मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। न्यूजीलैंड जैसे विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश के साथ व्यापक व्यापारिक समझौता भारत की आर्थिक कूटनीति की बढ़ती सक्रियता को दर्शाता है। भारत हाल के वर्षों में अनेक व्यापारिक साझेदारों के साथ समझौतों को आगे बढ़ा रहा है। सरकारी अभिलेखों के अनुसार भारत ने 16 मुक्त व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं; हालांकि नए समझौतों में से कुछ 20 सितंबर

अपने ही बुने जाल में फंसा चुनाव आयोग

दिल्ली में वोटर लिस्ट के विशेष महान पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद लगभग 47 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से बाहर हो गए हैं। मैपिंग और मिसमैच पर 33 लाख से ज्यादा मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है, पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, विदेश मंत्री एस जयशंकर, सांसद और वरिष्ठ अधिकृत कपिल सिब्बल, सेना के पूर्व ऑपरेटिव, चुनाव आयुक्त एसएस संधु, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की पत्नी, पूर्व जस्टिस रंजना देसाई, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद, उर्दूक सचिव रजत कुमार मिश्रा, सीएजी संजय मुर्ति, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सहित हजारों छिछोरीआईबी के नाम मतदाता सूची में नहीं हैं।

इन सभी को चुनाव आयोग द्वारा नोटिस जारी किए गए हैं। इसके बाद एसआईआर प्रक्रिया और कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर का कपाल दिल्ली सहित सारे देश ने देख लिया है। 10 जुलाई 2025 से सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। तारीख पर तारीख पड़ रही है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने एसआईआर के माध्यम से विभिन्न राज्यों के 13 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं को मतदाता सूची से हटा दिया है। बिहार, पश्चिम बंगाल इत्यादि राज्यों में एसआईआर के लाखों मतदाताओं के नाम काटे गए, उसके बाद मतदान हुआ। बिहार में भारतीय जनता पार्टी की पहली बार सरकार बन गई। इसके बाद पश्चिम बंगाल के चुनाव हुए, वहां पर भाजपा की पूर्ण बहुमत से सरकार बन गई। पिछले डेढ़ 2 वर्षों से चुनाव आयोग की कार्य प्रणाली और एसआईआर को लेकर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी यह मामला 1 वर्ष से अधिक से चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर की प्रक्रिया, एसआईआर के लिए बनाए गए नियम जो हर राज्य के लिए अलग-अलग लागू किए जा रहे हैं। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में समय-समय पर आपति दर्ज करवाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को वैधानिक बता दिया। चुनाव के कुछ महीने पहले जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उन राज्यों में एसआईआर करने की प्रक्रिया को ठीक बता दिया। चुनाव आयोग ने जिन लोगों के नाम काटे, उनके

नाम उजागर नहीं किये, नोटिस कंप्यूटर के जरिए भेजे जा रहे हैं। कंप्यूटर मतदाता सूची की जांच कर रहे हैं। उसका सॉफ्टवेयर चुनाव आयोग ने बनवाया है। कैसे सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, यह भी चुनाव आयोग राजनैतिक दलों को नहीं बताता है।



सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को मिली संवैधानिक शक्तियों के कारण उसे सर्वशक्तिमान मान लिया है। चुनाव आयोग लगातार मममजी करता चला जा रहा है। इसकी आंच अब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तक पहुंचने लगी है। कहा जा रहा है, जब गृह मंत्रालय में जस्टिस सूर्यकांत की

पदोन्नति को लेकर जो फाइल आईबी की ओर से गई थी, उस समय गृह मंत्रालय ने आईबी की जांच को प्रधानता नहीं दी। पंजाब हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सूर्यकांत की पदोन्नति को लेकर एक अहम भूमिका ज्ञानेश कुमार की थी। इस तरह के आरोप अब

एसआईआर का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। बिहार एवं पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो गया है। अब रही सही कसर कंप्यूटर से जो मतदाता सूची तैयार की जा रही है, उसमें बड़े-बड़े महारथियों के नाम आसानी से काटे जा रहे हैं, या उन्हें नोटिस जारी हो रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश का परिवार, वरिष्ठ अधिकृत कपिल सिब्बल भी एसआईआर के शिकार हो गए हैं। जिसके कारण एसआईआर अब तूल पकड़ गया है। केंद्रीय चुनाव आयोग को इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। करोड़ों मतदाताओं से उनके नागरिक अधिकार छीन लिए गए हैं। जिन नागरिकों के नाम मतदाता सूची में नहीं हैं, उन्हें राज्य शासन से मिलने वाली सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। जगह-जगह उन पर अड़गे लगाए जा रहे हैं। बंगाल के एक संपादक महोदय के पासपोर्ट का नवीनीकरण नहीं हुआ, जिसके कारण वह अपनी बेटी की शादी में नहीं जा पाए। सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है, सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुका है, नागरिकता तय करने का अधिकार चुनाव आयोग के पास नहीं है। उसके बाद भी यह खेल लगातार खेला जा रहा है। पश्चिम बंगाल में सुप्रीम कोर्ट ने अपने विशेष अधिकार का उपयोग करते हुए पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के जजों को भी मामले सुनने के काम में लगा दिया। 38 लाख अपीलों में 91 फीसदी 1 लाख अपीलों की सुनवाई हुई है। इसमें 31 फीसदी मतदाता सही पाए गए हैं। अभी भी 37 लाख लोग डिब्बल के चक्कर लगा रहे हैं। इसको निपटने में 20 वर्षों से

अधिक का समय लगेगा। रोज कमाने खाने वाले उन करोड़ों लोगों को चुनाव आयोग ने मतदाता सूची से बाहर करके उनके नागरिक अधिकार में डंका डाल दिया है। सुप्रीम कोर्ट सारी बातों को सुन रही है, देख रही है, समझ रही है। उसके बाद भी किन कार्यों से तारीख पर तारीख देकर मामले को डाल रही है। इसको लेकर अब देश में आक्रोश देखने को मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के वकील भी सड़कों पर उतर रहे हैं। हाल ही में दिल्ली में जो एसआईआर हुई है, उसने चुनाव आयोग को अपने ही बुने जाल में बुरी तरह से फंसा दिया है।

आयुक्त ज्ञानेश कुमार इस जाल से कैसे बाहर निकल पाएंगे, इसकी चर्चा अब सारे देश में हो रही है। अभी तक मतदाता चुप था। समझ नहीं पा रहा था, कि वह अपनी लड़ाई कैसे लड़े। अब 13 करोड़ से ज्यादा लोग नागरिक अधिकार से वंचित हो गए हैं। यह अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए यदि सड़कों पर आ जाएंगे, तो क्या होगा? इसका आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है। कानून और नियमों का पालन तभी तक होता है, जब लोगों को उस पर विश्वास हो। यदि विश्वास खल हो जाता है, तो कोई भी नियम कानून का पालन कराना किसी भी सरकार और अदालत के बस की बात नहीं होती है। केंद्रीय चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर गंभीरता से विचार करें। स्वतंत्रता के बाद से अभी तक हर बार बीएलओ घर-घर जाकर सत्यापन करते थे। निर्वाचन अधिकारी अपने क्षेत्र की मतदाता सूची के प्रति जिम्मेदार होते थे।

महिलाओं की आजीविका से बच्चों के भविष्य तक-जमीनी हकीकत जानने पहुंचीं जिला पंचायत अध्यक्ष

मड़ीसरई में दीदियों के बीच बैठकर सुनीं आजीविका की बातें, बड़वाही कन्या आश्रम में बच्चों से पढ़ाई, भोजन और सुविधाओं पर सीधा संवाद

मीडिया ऑडिटर, एमसीबी (निप्र)। गांव की महिलाओं के हाथों में चल रही आजीविका की गतिविधियां हों या आश्रम में रहकर पढ़ाई कर रहे बच्चों के सपने-जिला पंचायत अध्यक्ष यशवंती सिंह ने मंगलवार को दोनों की जमीनी तस्वीर करीब से देखी विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका की गारंटी मिशन (ग्रामीण) योजना की समीक्षा के बाद विकासखंड भरतपुर के भ्रमण पर निकलीं जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा महिला समूहों के बीच बैठकर उनकी मेहनत और कमाई की जानकारी ली, तो कहीं बच्चों के बीच पहुंचकर उनकी पढ़ाई, भोजन और रहन-सहन की व्यवस्थाओं को परखा ग्राम पंचायत मड़ीसरई में आयोजित दोदी मिलन कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष ने महिला स्व-सहायता समूहों की सदस्यों से सीधे संवाद किया। उन्होंने समूहों द्वारा संचालित आजीविका गतिविधियों, किए जा रहे कार्यों और उनसे मिल रहे लाभ की जानकारी ली। महिलाओं ने अपने काम, अनुभव और समूह के



माध्यम से आगे बढ़ने की कहानी साझा की अध्यक्ष ने उनकी बातों को गंभीरता से सुना और गतिविधियों की कार्यप्रणाली को समझा। दीदी मिलन कार्यक्रम महिलाओं के लिए केवल मुलाकात का मंच नहीं, बल्कि अपने अनुभव साझा करने और सामूहिक प्रयासों से आगे बढ़ने का अवसर भी बना इसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष कन्या आश्रम बड़वाही पहुंचीं निरीक्षण के दौरान उन्होंने औपचारिकता से अलग

बच्चों के साथ सहज माहौल में बैठकर बातचीत की बच्चों से उनकी पढ़ाई, पसंदीदा विषय, रोजमर्रा की दिनचर्या, भोजन और आश्रम में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में पूछा। बच्चों ने भी पूरे उत्साह से अपनी बातें साझा कीं किसी ने पढ़ाई से जुड़ी बात बताई तो किसी ने आश्रम की दिनचर्या के बारे में जानकारी दी अध्यक्ष ने बच्चों की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और उनकी जरूरतों को समझने का प्रयास किया आश्रम



निरीक्षण के दौरान केवल शैक्षणिक व्यवस्था तक सीमित न रहते हुए भोजन स्वास्थ्य रहने और बच्चों की बेहतर देखभाल से जुड़ी व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया गया बच्चों को उपलब्ध सुविधाओं और उनकी आवश्यकताओं की जानकारी ली गई ताकि उनके लिए सुरक्षित और सुविधाजनक वातावरण सुनिश्चित किया जा सके जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि बच्चों को ऐसा सकारात्मक वातावरण

मिलना जरूरी है, जहां वे बिना किसी चिंता के मन लगाकर पढ़ाई कर सकें और अपने भविष्य के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकें जिला पंचायत अध्यक्ष का यह भ्रमण गांव की दो महत्वपूर्ण तस्वीरों को सामने लाने वाला रहा एक ओर महिला समूहों के माध्यम से महिलाएं आजीविका से जुड़कर आगे बढ़ने का प्रयास कर रही हैं वहीं दूसरी ओर आश्रम में बच्चे शिक्षा के जरिए अपने भविष्य की नींव तैयार कर रहे हैं

महिलाओं और बच्चों से सीधे संवाद के माध्यम से उनकी समस्याओं, जरूरतों और उपलब्ध सुविधाओं को करीब से समझने का प्रयास किया गया यह दौरा योजनाओं की समीक्षा से आगे बढ़कर जमीन पर उनके असर और जरूरतों को सीधे जानने का अवसर भी बना इस अवसर पर अनीता चौधरी, जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र क्रमांक 01, भरतपुर सहित जनप्रतिनिधि एवं अन्य उपस्थित रहे।

58 बॉन्ड डॉक्टरों की नियुक्ति, PHC-CHC में दूर होगी कमी

30 डॉक्टरों ने अब तक ली जॉइनिंग, 25 सितंबर तक सभी को करना होगा कार्यभार ग्रहण जिले में करीब 200 डॉक्टर होंगे

मीडिया ऑडिटर, नर्मदापुरम (निप्र)। जिले की सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए 58 बॉन्ड डॉक्टरों की पोस्टिंग की गई है। एमबीबीएस डॉक्टरों की जॉइनिंग प्रक्रिया मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) कार्यालय में जारी है सभी डॉक्टरों को 25 सितंबर तक जॉइनिंग लेना अनिवार्य किया गया है सीएमएचओ डॉ. नरसिंह गहलोत ने बताया कि 58 में से 30 डॉक्टर अब तक जॉइन कर चुके हैं शेष डॉक्टर भी प्रतिदिन सीएमएचओ कार्यालय पहुंचकर जॉइनिंग प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं जरूरत के अनुसार इन डॉक्टरों को जिला अस्पताल, सिविल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (टा।ए) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) में पदस्थ किया जाएगा सीएमएचओ ने बताया कि सभी बॉन्ड डॉक्टर एमबीबीएस हैं मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के समय ग्रामीण क्षेत्र में एक वर्ष सेवा देने की शर्त के तहत बॉन्ड लिया जाता है डिग्री पूरी होने के बाद इसी प्रावधान के तहत डॉक्टरों को सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में पदस्थ किया जा रहा है पदस्थ डॉक्टर नियमानुसार मरीजों की जांच, उपचार और आवश्यक



दवाइयां लिख सकेंगे उन्हें स्वास्थ्य विभाग के निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार सेवाएं देनी होंगी। ग्रामीण क्षेत्रों के का।ए और टा।ए में डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ने से स्थानीय मरीजों को उपचार की सुविधा मिलने में मदद मिलेगी जिले में करीब 200 डॉक्टर होंगे डॉ. गहलोत के अनुसार जिले के सरकारी अस्पतालों में वर्तमान में 114 डॉक्टर कार्यरत हैं पिछले महीने 27 नए डॉक्टरों ने भी जॉइन किया था अब 58 बॉन्ड डॉक्टरों की जॉइनिंग होने से सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में डॉक्टरों की संख्या करीब 200 तक पहुंच जाएगी स्वास्थ्य विभाग द्वारा डॉक्टरों को आवश्यकता के अनुसार विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में पदस्थ किया जाएगा इससे विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकीय सेवाओं को मजबूत करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

दूसरी संतान बालिका होने पर रामकली को मिला 6 हजार रुपये का लाभ सेवा संकल्प अभियान के तहत सामने आई रामकली की कहानी, बेटे के जन्म पर PMMVY से मिला 6 हजार रुपये का सहारा



मीडिया ऑडिटर, एमसीबी (निप्र)। सेवा संकल्प अभियान के तहत जिले में जनकल्याणकारी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध

कराने के साथ मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य तथा पोषण को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण योजना है जिले के खड़गवा विकासखंड के ग्राम कदरेवा निवासी रामकली को भी इस योजना का लाभ मिला है। उनकी दूसरी संतान बालिका होने पर उन्हें योजना के तहत 6 हजार रुपये की एकमुश्त आर्थिक सहायता प्राप्त हुई है। रामकली ने बताया कि दूसरी संतान के रूप में बेटे के जन्म के बाद गांव की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा उन्हें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में जानकारी दी गई कार्यकर्ता ने योजना की पात्रता और मिलने वाले लाभ के बारे में विस्तार से समझाया तथा उनका

आवेदन भी भरवाया निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें 6 हजार रुपये की सहायता राशि प्राप्त हुई रामकली ने बताया कि योजना के माध्यम से मिली आर्थिक सहायता उनके लिए उपयोगी रही। उन्होंने योजना का लाभ दिलाने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री निष्णु देव साय को धन्यवाद दिया प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र महिलाओं को पहली जीवित संतान के लिए 5 हजार रुपये की सहायता राशि निर्धारित प्रावधानों के अनुसार किस्तों में दी जाती है वहीं दूसरी संतान बालिका होने पर 6 हजार रुपये की एकमुश्त

सहायता राशि देने का प्रावधान है रामकली जी को इसी प्रावधान के तहत दूसरी संतान बालिका होने पर 6 हजार रुपये का लाभ मिला है मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को बढ़ावा देना योजना का उद्देश्य योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को उचित पोषण के लिए प्रोत्साहित करना, गर्भावस्था के दौरान आवश्यक प्रसव पूर्व जांच (ANC) और संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना तथा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार लाना है इसके साथ ही गर्भावस्था के दौरान होने वाली संभावित आय की क्षति को आर्थिक भारपाई के रूप में भी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

30 साल से सरकारी योजनाओं से वंचित दिव्यांग बैगा महिला, जनसुनवाई में लगाई गुहार आउटसोर्स कर्मचारियों ने भी सौंपा ज्ञापन, वेतन और ईपीएफ-ईएसआईसी में अनियमितताओं की शिकायत

मीडिया ऑडिटर, अनूपपुर (निप्र)। जिला कलेक्ट्रेट में मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में 52 आवेदकों ने अपनी समस्याएं प्रशासन के सामने रखीं इस दौरान कोतमा तहसील के थानगांव कुदरी हरटोला निवासी करीब 60 वर्षीय दिव्यांग बैगा महिला गीता बैगा अपने परिवार के साथ पहुंचीं उन्होंने आरोप लगाया कि वह करीब 30 वर्षों से सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हैं गीता बैगा के अनुसार उन्हें अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है पंचायत स्तर पर आधार कार्ड भी नहीं बन पाया और बैगा परिवारों के लिए मिलने वाली 1000 रुपए की आर्थिक सहायता से भी वह वंचित हैं उन्होंने बताया कि पहले बिजुरी नगरपालिका क्षेत्र में रहने के दौरान भी उन्हें योजनाओं का लाभ नहीं मिला। बाद में थानगांव ग्राम पंचायत में रहने लगीं लेकिन यहां भी समस्या का



समाधान नहीं हुआ उन्होंने कलेक्टर से योजनाओं का लाभ दिलाने की मांग की 14 साल बाद भी नहीं मिला मुआवजा जैतहरी तहसील के गुआंरी गांव निवासी संतोष राम राठौर ने भी कलेक्टर को आवेदन सौंपा उन्होंने बताया कि मोजरबेयर पावर प्लांट के लिए वर्ष 2010 में उनकी करीब 10 एकड़ जमीन ली गई थी, लेकिन अब तक मुआवजा और

रोजगार नहीं मिला अगस्त में उन्होंने रोजगार व मुआवजे की मांग पूरी नहीं होने पर आत्महत्या की चेतावनी भी दी थी इसके बावजूद समस्या का निराकरण नहीं होने का आरोप लगाया आउटसोर्स कर्मचारियों ने उठाई समस्याएं मध्य प्रदेश राज्य आउटसोर्स कर्मचारी संघ ने जिलाध्यक्ष चंद्रप्रकाश तिवारी के नेतृत्व में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि उनसे कुशल काम लेने के बावजूद कारगजों में अकुशल बताकर कम वेतन दिया जा रहा है वेतन में देरी, पे-स्लिप नहीं देने, ईपीएफ-ईएसआईसी में कथित अनियमित कटौती बोनस नहीं देने और बिना नोटिस नौकरी से हटाने की शिकायत भी की गई संघ ने 12 सूत्रीय मांगों पर 9 अक्टूबर तक कार्रवाई की मांग की है प्रशासन ने जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों के निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।

करम की डाली, मांदर की थाप और रातभर थिरकता गांव... कर्मा पर्व में जीवंत होती है जनजातीय संस्कृति जाई की हरियाली में अच्छी फसल की उम्मीद, करम देवता की पूजा में परिवार की खुशहाली की कामना गीत-नृत्य में पीढ़ियों से सहेजी जा रही लोक विरासत

मीडिया ऑडिटर, एमसीबी (निप्र)। रात गहराती है... आंगन में करम की हरी डाली सजी है मिट्टी के दीपक की लौ टिमटिमा रही है मांदर की पहली थाप पड़ते ही सनटाटा टुटता है और गीतों की लय के साथ पूरा गांव जैसे एक सुर में बंध जाता है महिलाएं गोल घेरा बनाकर थिरकती हैं पुरुष मांदर, झांझ और मोहरी की धुन साधते हैं। कोई अच्छी फसल की कामना करता है कोई परिवार की खुशहाली की बच्चों की आंखों में उसव की चमक है और बुजुर्गों की जुवान पर पीढ़ियों पुरानी लोककथाएं यही कर्मा है। एक ऐसा लोकपर्व, जिसमें पूजा है तो प्रकृति के प्रति कृतज्ञता भी कृषि की उम्मीद है तो भाई-बहन के स्नेह की भावना भी और



सबसे बढ़कर पूरा समाज एक साथ खड़ा दिखाई देता है। एमसीबी और सरगुजा अंचल के जनजातीय जीवन में कर्मा पर्व केवल कैलेंडर की एक तारीख नहीं है यह खेत, जंगल परिवार और समाज के रिश्तों को फिर से जीवंत करने वाला उत्सव है करम वृक्ष की डाली से लेकर जाई की हरियाली तक और बैगा की कथा से लेकर मांदर की थाप तक-हर

परंपरा अपने भीतर लोकजीवन का एक अर्थ समेटे हुए है कर्मा पर्व की पहचान करम वृक्ष से है पर्व पर करम वृक्ष की डाली लाकर गांव के पटेल अथवा प्रमुख व्यक्ति के आंगन में स्थापित की जाती है इसे करम देवता का प्रतीक मानकर पूजा-अर्चना की जाती है यह सिर्फ एक पेड़ की डाली नहीं होती। जनजातीय लोकमान्यता में यह



प्रकृति, कृषि और समृद्धि का प्रतीक है। इसके सामने अच्छी फसल, अनुकूल वर्षा परिवार की खुशहाली और गांव के कल्याण की कामना की जाती है प्रकृति के साथ हमारे संबंध वाले जनजातीय समाज के लिए करम की डाली यह संदेश भी देती है कि जीवन और प्रकृति को अलग करके नहीं देखा जा सकता कर्मा पर्व का उत्सव एक दिन में शुरू नहीं

होता। इसकी तैयारी पहले से शुरू हो जाती है। तीजा के अवसर पर महिलाएं टोकरी में जौ, गेहूं, मक्का, धान और अन्य फसलों के बीज बोती हैं कुछ दिनों बाद यही बीज अंकुरित होकर हरी-हरी जाई का रूप लेते हैं। कर्मा पर्व तक जाई हरियाली से भर जाती है इसे फूलों से सजाया जाता है मिट्टी का दीपक जलाया जाता है और पूजा में अर्पित

किया जाता है एक छोटी-सी टोकरी में उगती यह हरियाली दरअसल खेतों में लहलहाती फसल की उम्मीद का प्रतीक है। बीज से अंकुर और अंकुर से फसल तक की यात्रा को जनजातीय समाज ने अपने लोकपर्व का हिस्सा बना लिया है लोकमान्यता में कर्मा को कर्मा और करम से जोड़कर देखा जाता है कर्मा यानी मेहनत और करम यानी भाग्य। संदेश सीधा हैकृमेहनत करते रहो, अच्छे कर्म करते रहो और शुभ फल की कामना करो करम देवता की कृषि, फसल, प्राकृतिक समृद्धि और सामुदायिक कल्याण से जोड़ा जाता है इसलिए यह पर्व खेतिहर समाज के लिए विशेष महत्व रखता है।

आंगनबाड़ी की एक जानकारी बनी उर्मिला का सहारा, मातृ वंदना योजना से मिला आर्थिक संबल

मीडिया ऑडिटर, एमसीबी (निप्र)। गर्भावस्था के दौरान आर्थिक जरूरतें बढ़ जाती हैं। ऐसे समय में शासन की एक छोटी-सी मदद भी परिवार के लिए बड़ा सहारा बन सकती है। मनेन्द्रगढ़ विकासखंड के ग्राम बौरीखंड निवासी उर्मिला जी के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना इसी तरह का संबल बनी। पहली संतान के जन्म पर उन्हें योजना के तहत 5 हजार रुपए की एक छोटी-सी मदद भी परिवार के लिए बड़ा सहारा बन सकती है। मनेन्द्रगढ़ विकासखंड के ग्राम बौरीखंड निवासी उर्मिला जी के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना इसी तरह का संबल बनी। पहली संतान के जन्म पर उन्हें योजना के तहत 5 हजार रुपए की आर्थिक सहायता मिली, जिससे मातृत्व के इस महत्वपूर्ण दौर में उन्हें आर्थिक सहारा मिला उर्मिला जी बताती हैं कि गर्भावस्था के दौरान गांव की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने उन्हें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) के बारे में जानकारी दी। उन्हें बताया गया कि पात्र गर्भवती महिलाओं को योजना के तहत आर्थिक सहायता दी जाती है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने पात्रता और लाभ की जानकारी देने के साथ आवेदन प्रक्रिया पूरी करने में भी

सहयोग किया। निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद उर्मिला को योजना के तहत 5 हजार रुपए की सहायता राशि प्राप्त हुई उनके लिए यह राशि गर्भावस्था और मातृत्व के दौरान आने वाली जरूरतों को पूरा करने में उपयोगी साबित हुई उर्मिला जी ने बताया कि उन्हें योजना की जानकारी समय पर मिली और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने आवेदन से लेकर लाभ मिलने तक सहयोग किया। आर्थिक सहायता प्राप्त होने पर उन्होंने शासन की योजना के प्रति संतोष जताया और जानकारी देने तथा लाभ प्राप्त करने में सहयोग के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के प्रति आभार व्यक्त किया उर्मिला की कहानी यह भी बताती है कि जब योजनाओं की जानकारी गांव तक पहुंचती है और मैदानी स्तर के कार्यकर्ता हितग्राही को आवेदन की प्रक्रिया में सहयोग करते हैं, तो शासकीय योजनाओं का लाभ जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचना आसान हो जाता है।

बेटियों ने रचा इतिहास

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को 147 रनों से हराकर एशियाई खेलों में पहला स्वर्ण जीता

नागोया ,एजेसी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशियाई खेलों के फाइनल मुकाबले में श्रीलंकाई टीम को 147 रनों से हराकर अपना खिताब बरकरार रखने के साथ ही देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारतीय टीम का एशियाई खेलों में ये लगातार दूसरा स्वर्ण पदक है। पिछली बार भी भारतीय महिला टीम ने इन खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इस बार 147 रनों से जीत के साथ ही नया रिकार्ड भी अपने नाम किया है। ये टी20 अंतरराष्ट्रीय में रनों के हिसाब से यह उसकी अब तक की सबसे बड़ी जीत है। इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए स्मृति मंधाना के अर्धशतक 79 रन और शेफाली वर्मा के 48 रनों व ऋचा घोष के 49 रनों की सहायता से 20 ओवरों में 3 विकेट पर 216 रन बनाये। भारतीय टीम ने पावरप्ले का पूरा फायदा उठाते हुए शुरुआती में ही बिना किसी नुकसान के छह ओवर में 59 रन बना दिये। मंधाना और

शेफाली के बीच 99 रन की साझेदारी हुई। वहीं श्रीलंकाई टीम को जीत के लिए 217 रनों का लक्ष्य मिला। इसका पीछा करते हुए लंकाई टीम केवल 69 रन ही बना पायी। श्रीलंका की ओर से केवल कप्तान चामरी अयापट्टु ही 29 रन व कविशा दिलहारी 11 रन बना पायी। वहीं अन्य खिलाड़ी एक के बाद एक आउट होती गयीं। भारत की ओर से दीप्ति शर्मा ने तीन जबकि शेफाली वर्मा, श्रेयका पाटिल और श्री चरणी ने दो दो विकेट लिए। ये हार श्रीलंका महिला टीम की टी20 अंतरराष्ट्रीय इतिहास की सबसे बड़ी हार है। इससे पहले श्रीलंका को 2019 में नॉर्थ सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 132 रनों से सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा था।

इस मुकाबले के साथ ही भारतीय महिला टीम ने टी20 अंतरराष्ट्रीय में अपनी लगातार 8वीं जीत हासिल कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। ये इस प्रारूप में भारतीय टीम की अब तक की सबसे बड़ी जीत है। इससे भारतीय टीम ने साल 2018 में बनाए गए लगातार 7



जीत के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। गौरतलब है कि श्रीलंकाई टीम ने भारतीय टीम को अंतिम बार 2024 एशिया कप के फाइनल में हराया था, लेकिन उसके बाद से भारतीय टीम ने श्रीलंका के खिलाफ लगातार आठों टी20 मुकाबलों में जीत दर्ज की है।

आज के खेल का आकलण मंधाना की 45 गेंद में 79 रन जबकि ऋचा घोष की 22 गेंद में नाबाद 49 रनों की पारी रही। दूसरी ओर 5 श्रीलंकाई गेंदबाजी आज विफल रही। ऐसे में भारतीय टीम एशियाई

खेलों के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बनाने में सफल रही। . शेफाली और स्मृति दोनों ने स्पिनरों की जमकर धुनाई की. स्मृति ने तीसरे ओवर में बाएं हाथ की स्पिनर सुमृधिका कुमारी की लगातार गेंदों पर दो छक्के लगाये। इसके बाद तेज गेंदबाज मिताली अयोध्या का ओवर और भी महंगा साबित हुआ। मंधाना ने इस मैच में कुल सात छक्के लगाए। वहीं शेफाली अर्धशतक के करीब आकर भी उसे पूरा नहीं कर पायीं।

भारतीय अंडर-19 क्रिकेट टीम ने दूरे टी20 में भी ऑस्ट्रेलियाई टीम को हराया

यशबर्धन और विनीत का शानदार प्रदर्शन

सौराष्ट्र ,एजेसी। यशबर्धन चौहान के शतक से भारतीय अंडर-19 क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे मैच को आसानी से जीत लिया। भारतीय टीम की ओर से यशबर्धन ने 103 रन जबकि वीके विनीत ने 87 रन बनाये। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है। इस मैच में भारतीय गेंदबाजों का प्रदर्शन भी काफी अच्छा रहा और उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई टीम को 238 रनों पर ही रोक दिया।

इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने निर्धारित 50 ओवरों में सात विकेट पर 341 रन बनाये। सलामी बल्लेबाज आर्यवीर सहवाग ने 47 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें कप्तान लक्ष्य रायचंदानी 11 के साथ पहले विकेट के लिए 46 रन की साझेदारी और फिर वीके विनीत के साथ दूसरे विकेट के लिए 55 रन की साझेदारी की। आर्यवीर बदकिस्मती से रन आउट हो गए। वहीं पहले मैच में 18 गेंदों पर 38 रन बनाने वाले अन्वय द्रविड़ इस मुकाबले में केवल 9 रन ही बना पाये।



सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त मिली

इसके बाद यशबर्धन और विनीत ने तीसरे विकेट के लिए 132 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी कर पारी को संभाला। यशबर्धन ने केवल 100 गेंदों में 15 चौके और 2 छक्कों की मदद से 122 रन बनाए, जबकि विनीत ने 92 गेंदों पर छह छक्के और चार चौकों के

साथ 87 रन बनाये। अंतिम ओवरों में कुशाग्र ओझा ने भी 20 गेंदों में पांच चौकों और एक छक्के की मदद से 34 रन बनाए, जिससे भारतीय अंडर-19 टी 341 रन तक पहुंचने में सफल रही। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से थॉमस वासेओ ने 78 रन देकर तीन जबकि

पैट्रिक सुलिवन ने 55 रन दे कर दो विकेट लिए।

वहीं 342 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम शुरुआत से ही लड़खड़ा गई। भारतीय गेंदबाजों ने नियमित अंतराल पर विकेट लेकर मेहमान टीम को उबरने का अवसर ही नहीं दिया। वापसी का मौका नहीं दिया।

ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कप्तान जैक चोस्नेक ने सबसे अधिक 81 रन (63 गेंद) बनाए, जबकि मैथ्यू लॉघ (42) और ब्लेक कैटल ने भी पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था। अंततः पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम 41.1 ओवर में 238 रन पर ऑल आउट हो गई। भारतीय गेंदबाजी में चिगुरुपति वेंकट सबसे सफल रहे, जिन्होंने 64 रन देकर तीन विकेट लिए, जबकि काव्या पटेल और यशबर्धन चौहान ने दो-दो विकेट हासिल किए। मोहित उल्वा, मनल चौहान और यशवीर गौड़ को भी एक-एक सफलता मिली।

भारत ने इससे पहले वर्षा बाधित पहले मैच को 20-20 ओवर का कर दिए जाने के बाद सात रन से जीता था। इस जीत से भारतीय टीम ने तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है।

जापान के खिलाफ अभिषेक शर्मा हुए गोल्डन डक



सानो ,एजेसी। जापान के सानो में भारत और जापान के बीच राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित ऐतिहासिक टी-20 मैच का आगाज कुछ ऐसा रहा, जिसकी कल्पना शायद ही किसी क्रिकेट प्रशंसक या पंडित ने की होगी। इस विशेष मुकाबले से पहले, हर कोई यही सोच रहा था कि भारतीय टीम अपने अनुभव, प्रतिभा और टी-20 क्रिकेट के जबरदस्त इतिहास के दम पर जापान के अनुभवहीन गेंदबाजों पर हावी होगी। छोटे ग्राउंड का पूरा फायदा उठाते हुए भारतीय बल्लेबाज रनों का अंबार लगाएंगे और मैच एकतरफा साबित होगा। लेकिन, जब मैच शुरू हुआ तो मैदान पर नजारा बिलकूल उलट था, जिसने सभी को चौंका दिया। भारतीय पारी की पहली ही गेंद पर, युवा और विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा गोल्डन डक का शिकार होकर पवेलियन लौट गए। जापान के एक अपेक्षाकृत नौसिखिए गेंदबाज ने उन्हें बच्चे की तरह आउट कर भारतीय खेमे में शुरुआती क्षणों में ही मनसुनी फैला दी। यह घटना मैच के पहले ही ओवर में हुई, जब हर भारतीय फैन एक ताबड़तोड़ शुरुआत की उम्मीद कर रहा था। बाएं हाथ के इस प्रतिभाशाली बल्लेबाज से भारतीय फैस को बड़ी पारी की उम्मीद थी, खासकर जब मैच बारिश से प्रभावित होने के कारण पांच-पांच ओवर का कर दिया गया था और हर गेंद निर्णायक महत्व रखती थी। लेकिन दुर्भाग्यवश, अभिषेक क्रीज पर टिक भी नहीं पाए। जैसे ही गेंद उनके बल्ले के पास से गुजरी, स्टंप्स की गिल्लियां बिखर गईं और अभिषेक को बिना खाता खोले ही पवेलियन की ओर लौटना पड़ा। यह न सिर्फ अभिषेक के लिए एक बड़ा व्यक्तिगत झटका था, बल्कि पूरी भारतीय टीम के लिए भी एक अवश्रवसनीय शुरुआत थी, जिसने शुरुआती आत्मविश्वास को पूरी तरह से डगमगा दिया।

भारतीय टीम को जापान से जीत में आया पसीना

अंतिम गेंद पर 2 रन से जीत मिली



सानो ,एजेसी। भारत और जापान की पुरुष क्रिकेट के बीच यहां खेले गये ऐतिहासिक टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में भारतीय टीम को बड़ी मुश्किल ने 2 रनों से जीत मिली। जापान के सानों में हुए इस रोमांचक मुकाबले में अंतिम गेंद तक संघर्ष चला। यह मुकाबला भारत और जापान के बीच राजनीतिक संबंधों के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मारुति-सुजुकी कप के तहत खेला गया था। यह मैच, उम्मीद से कहीं ज्यादा रोमांचक और अप्रत्याशित साबित हुआ। किसी ने नहीं सोचा था कि तीन बार की विश्व चैंपियन भारतीय टीम को एक नई टीम के खिलाफ जीत के लिए इतना संघर्ष करना पड़ेगा। मैच की शुरुआत ही अप्रत्याशित हालातों का सामना करना पड़ा। चक्रवात और खराब मौसम के चलते मैदान गीला था, जिसने 20-20 ओवर के मुकाबले को केवल पांच-पांच ओवर का किया गया। इन विषम परिस्थितियों में, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम के लिए मुश्किलें और बढ़ गईं। पिच धीमी और टर्निंग थी, जिस पर भारतीय बल्लेबाजों को रन बनाने के लिए जमकर पसीना बहाना पड़ा। भारतीय टीम पांच ओवर में चार विकेट पर केवल 32 रन ही बना पाई। यह स्कोर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में किसी भी शीर्ष टीम के लिए बेहद कम माना जाता है। कप्तान श्रेयस अय्यर ने 12 गेंदों में सबसे अधिक 16 रन बनाये। उनके अलावा कोई भी भारतीय बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सका। अभिषेक शर्मा खाता भी नहीं खोल पाए, जबकि संजु सैमसन ने सात गेंदों में नौ और ईशान किशन ने छह गेंदों में सिर्फ तीन रन बनाए। बड़े शॉट्स लगाने की कोशिश में भारतीय खिलाड़ी लगातार विकेट आउट होते गये। इसके बाद जापानी टीम लक्ष्य का पीछा करने उतरी। जापानी बल्लेबाजों ने भी धीमी पिच पर भारतीय बल्लेबाजों जैसी गलतियों की पर उन्होंने हर गेंद पर रन बनाये के प्रयास किये। उसने अपने खेल से भारतीय टीम को घुटनों पर आने मजबूर कर दिया।

भारतीय महिला कबड्डी टीम ने बांग्लादेश को हराकर अपना अभियान शुरु किया

आइची ,एजेसी। भारतीय महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में अपने अभियान की जीत से शुरुआत करते हुए पहले ही मुकाबले में बांग्लादेश को 42-21 से हराया है। भारतीय टीम ने टोकाई सिटिजन्स जिम्नेजियम में खेले गए ग्रुप-ए के अपने पहले मुकाबले में बांग्लादेश को 42-21 के बड़े अंतर से हराकर अपने इरादे जाहिर कर दिये हैं। इस जीत से तय है कि टीम लगातार तीसरे एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने की दायेंदार है।

इस मुकाबले में भारतीय टीम ने रक्षात्मक रणनीति अपनाते हुए लगातार आक्रामक रुख अपनाया। भारतीय खिलाड़ियों के अच्छे तालमेल के कारण बांग्लादेश की टीम खेल के किसी भी चरण में ऊपर नहीं आ पायी। खासकर संजू देवी ने रेडिंग में अपने बेहतरीन प्रदर्शन से टीम को लगातार अंक दिलाए। भारतीय टीम ने मैच की शुरुआत से ही अपना दबाव कायम कर लिया था। ऐसे में बांग्लादेशी रेडर्स के लिए बोनस लाइन तक पहुंचना भी कठिन हो गया। भारतीय रेडर्स ने लगातार सफल रेड करते हुए अंक बढ़ाये। वहीं, डिफेंस में मनीषा कुमारी लेफ्ट कवर से



बेहद प्रभावी रहीं, जिन्होंने कई महत्वपूर्ण टैकल किए। अटैक में सोनाली शिगेट और कप्तान पुष्पा राणा ने भी

अपने अनुभव का लाभ उठाते हुए महत्वपूर्ण अंक हासिल किए। भारतीय टीम की इस शानदार रणनीति

एशियन खेलों में सुचिका को कांस्य पदक मिलने से संतुष्ट नहीं परिवार

बोला, उसे कम से कम रजत तो मिलना चाहिये था



रोहतक ,एजेसी। भारतीय मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स (एमएमए) फाइटर सुचिका तरियाल को जापान में जारी एशियाई खेलों में कांस्य पदक मिला है। वहीं सुचिका का परिवार इससे संतुष्ट नहीं है और उसका मानना है कि सुचिका का प्रदर्शन जिस स्तर का था उससे उसे कम से कम रजत पदक मिलन चाहिये थे। सुचिका को महिलाओं के 60 किग्रा वर्ग में कांस्य पदक मिला है। सुचिका को सेमीफाइनल में एक विवादित फैसले के बाद हार हुआ घोषित किया गया जिसको लेकर परिवार में नाराजगी है। परिवार का मानना है कि वह इससे कहीं बेहतर परिणाम की अधिकारी थी। गौरतलब है कि उत्तराखंड की मूल निवासी सुचिका की शादी हरियाणा में हुई थी। बहू की इस कामयाबी पर सुचिका की सास ने अपनी अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहा, सुचिका ने शुरू से ही लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है और वह हर मुकाबले में पूरी ताकत के साथ बनी रही हैं। 2022 में भी वह चौथे स्थान पर रही थीं, और तब भी उन्हें लगा था कि वह बेहतर परिणाम की अधिकारी थीं। अब वह तीसरे स्थान पर रही हैं, हालांकि उन्हें लगा

कि उन्हें दूसरा स्थान मिलना चाहिए था। मुझे नहीं पता कि वेट कैटेगरी का मूल्यांकन कैसे किया गया, लेकिन देश के लिए पदक जीतने का उनका जज्बा हमेशा से मजबूत रहा है। हालांकि सुचिका कांस्य से खुश नहीं है। सिंगापुर की हुई हून टून के खिलाफ सेमीफाइनल में वह मुकाबले में पूरी तरह से हावी थीं पर इसके बावजूद उसे हारा हुआ घोषित कर दिया गया।

एशियाई खेलों में पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीम ने कांस्य पदक जीता

बांग्लादेश को 31 रनों से हराया



कोरोगी ,एजेसी। पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम ने एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता है। पाक महिलाओं ने यहां तीसरे स्थान के लिए हुए एक रोमांचक मुकाबले में बांग्लादेश को 31 रनों से हराकर ये पदक जीता। इस मुकाबले में पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। पाक टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 145 रन बनाए थे। कप्तान फातिमा सना ने सबसे

अधिक 45 रन बनाये। फातिमा ने अपनी पारी में 3 छक्के और 3 चौके लगाए। इसके अलावा, गुल फिरोजा ने 23 गेंदों पर 31, आलिया रियाज ने 22 गेंदों पर 25 रन की पारी खेली, और शावाल जुल्फिकार ने 17 रन बनाए। वहीं बांग्लादेश की ओर से नाहिदा अख्तर, शोरना अख्तर और औप रिंतु मोनी ने 2-2 विकेट लिए। संजीदा को 1 विकेट मिला।

इसके बाद जीत के लिए मिले 146 रनों

के लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 114 रन ही बना पायी। इस प्रकार उसे हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही बांग्लादेश की टीम चौथे पर रही।

बांग्लादेश की ओर से शरमोन अख्तर ने 45 गेंदों पर 4 चौकों की मदद से 46 रन बनाये पर वह टीम को जीत नहीं दिला पायी। कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज निगार सुल्ताना ने 25 रन बनाए।

नमो सेवा-अनकही कहानियां : छात्रों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 25 वर्षों की सेवा यात्रा का किया मंचन

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने दर्शक दीर्घा में बैठकर छात्र-छात्राओं का बढ़ाया उत्साह

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। सेवा संकल्प अभियान के तहत संत पूज्य प्रियदर्शी राम जी ऑडिटरियम पंजरी प्लाट रायगढ़ में 'नमो सेवा-अनकही कहानियां' कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डिग्री कॉलेज रायगढ़ के छात्र-छात्राओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्षों की यात्रा और देश के प्रति उनके योगदान पर आधारित जीवंत नाट्य प्रस्तुति दी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने दर्शक दीर्घा में बैठकर पूरी प्रस्तुति देखी और विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया।

नाट्य मंचन में सेवा, समर्पण और सामाजिक जिम्मेदारी का संदेश दिया गया। विद्यार्थियों ने अभिनय के माध्यम से विभिन्न परिस्थितियों और चुनौतियों के बीच लिए गए



निर्णयों तथा देश के विकास से जुड़े विषयों को मंच पर प्रस्तुत किया। प्रस्तुति की अतिथियों और दर्शकों ने सराहना की। 17 सितम्बर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि सेवा संकल्प अभियान 17 सितम्बर से 17 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है। अभियान के माध्यम से सेवा और जनभागीदारी से जुड़े विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि अभियान में 12 संकल्प और 25 सेवा कार्यों को शामिल किया गया है। इन गतिविधियों का उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों तक जनकल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के साथ लोगों को सेवा कार्यों से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी महत्वपूर्ण है। उन्होंने विद्यार्थियों की प्रस्तुति की सराहना करते हुए कहा कि युवाओं की ऊर्जा और रचनात्मकता समाज में सेवा और जिम्मेदारी की भावना को मजबूत कर सकती है। 25 वर्षों की यात्रा को मंच पर उतारा उप मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्षों की यात्रा को नाट्य रूप में प्रस्तुत किया है। कोरोना महामारी के कठिन दौर सहित विभिन्न परिस्थितियों का भी प्रस्तुति में उल्लेख किया गया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है।

संक्षिप्त समाचार



मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। सेवा संकल्प अभियान के तहत 'सेवा की कहानी' में जनकल्याणकारी योजनाओं से आम नागरिकों के जीवन में आ रहे बदलाव की तस्वीर सामने आ रही है। सरगुजा जिले के अम्बिकापुर विकासखंड के ग्राम सकालो चारपारा की मती रीता पात्र के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मिला गैस कनेक्शन ऐसी ही राहत लेकर आया है। पहले लकड़ी जुटाने और चूल्हे के धुएँ के बीच खाना बनाने में अधिक समय लगता था। अब गैस की सुविधा से रसोई का काम आसान हुआ है और बचा हुआ समय वे खेती-बाड़ी तथा परिवार के दूसरे जरूरी कामों में लगा पा रही हैं।

'लकड़ी के चूल्हे से गैस तक, बदली रसोई की तस्वीर': रीता पात्र अपने पति दशरथ पात्र और दो बच्चों के साथ रहती हैं। परिवार खेती-बाड़ी से जुड़ा है और दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं। रीता बताती हैं कि पहले भोजन लकड़ी के चूल्हे पर बनता था। इसके लिए नियमित रूप से लकड़ी की व्यवस्था करना पड़ती थी। खाना बनाने समय रसोई में धुआं भर जाता था और भोजन तैयार करने में भी काफी समय लगता था। सुबह बच्चों को स्कूल भेजने के लिए भोजन और टिफिन तैयार करने में अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती थी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन मिलने के बाद उनकी रसोई की पूरी दिनचर्या आसान हुई है। अब कम समय में भोजन तैयार हो जाता है और बच्चों का टिफिन भी समय पर बनाया जा सकता है। रीता कहती हैं, 'पहले हम चूल्हे पर खाना बनाते थे। लकड़ी लानी पड़ती थी और बहुत धुआं होता था। खाना बनाने में भी काफी समय लगता था। अब गैस मिलने से खाना और बच्चों का टिफिन जल्दी बन जाता है। हमें बहुत सुविधा हुई है।'

'रसोई में बचा समय अब खेत में दे रही योगदान': उज्ज्वला योजना से मिली सुविधा का असर केवल रसोई तक सीमित नहीं रहा। खाना बनाने में लगने वाला समय कम होने से रीता अब खेती-बाड़ी के कामों के लिए अधिक समय निकाल पा रही हैं। परिवार के कृषि कार्यों में उनका सहयोग बढ़ा है। पहले चूल्हे पर भोजन तैयार करने में अधिक समय लगने के कारण खेत के काम के लिए समय निकालना कठिन होता था, लेकिन अब रसोई का काम जल्दी पूरा होने से दिनचर्या बेहतर तरीके से व्यवस्थित हो रही है।

'धुएं से राहत और परिवार की दिनचर्या में आया बदलाव': गैस कनेक्शन मिलने से रीता को लकड़ी जुटाने की परेशानी और चूल्हे के धुएँ से राहत मिली है। बच्चों की स्कूल की तैयारी, भोजन और टिफिन बनाने से लेकर खेती-बाड़ी के कार्यों तक परिवार के दैनिक काम अब अधिक सहजता से हो पा रहे हैं। रीता पात्र ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति अभार व्यक्त करते हुए कहा कि गैस कनेक्शन से उनकी रोजमर्रा की एक बड़ी परेशानी दूर हुई है। रीता की कहानी बताती है कि सेवा संकल्प अभियान के तहत योजनाओं का लाभ जब जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचता है।

सेवा की कहानी: महतारी वंदन की राशि से यशोदा ने संवारा सिलाई का कारोबार



मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। सेवा संकल्प अभियान के तहत शासन की जनकल्याणकारी योजनाएं महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ उनके हुनर और स्वरोजगार को आगे बढ़ाने में सहायक बन रही हैं। सरगुजा जिले के ग्राम पंचायत सकालो की मती यशोदा प्रजापति की कहानी इसका उदाहरण है। सिलाई के हुनर को अपनी आजीविका का आधार बनाने वाली यशोदा ने महतारी वंदन योजना से मिलने वाली नियमित आर्थिक सहायता का उपयोग घरेलू जरूरतों के साथ बचत के लिए किया। छोटी-छोटी बचत से उन्होंने अपनी सिलाई की दुकान को धीरे-धीरे आगे बढ़ाया और परिवार की आर्थिक

जिम्मेदारियों में अपनी भागीदारी मजबूत की। 'महतारी वंदन की राशि से मिली बचत और कारोबार को संबल' यशोदा लंबे समय से सिलाई का काम कर रही हैं। सिलाई से होने वाली आय से वे परिवार की जरूरतों को पूरा करने में पति का सहयोग करती हैं। महतारी वंदन योजना से नियमित आर्थिक सहायता मिलने के बाद उनके लिए अपनी जरूरतों को पूरा करने के साथ कुछ राशि बचा पाना भी आसान हुआ। इसी बचत का उपयोग उन्होंने अपनी सिलाई की दुकान को आगे बढ़ाने में किया। यशोदा बताती हैं, 'महतारी वंदन का पैसा मिलता है तो उससे मुझे बहुत मदद हो जाती है। पैसे इकट्ठा करके धीरे-धीरे अपनी दुकान को आगे बढ़ाया है।'

'सिलाई से आय, बच्चों की पढ़ाई में भी सहयोग' यशोदा के पति वैन चलाते हैं और उनके दो बच्चे हैं। परिवार की जिम्मेदारियों के बीच यशोदा सिलाई का काम संभाल रही हैं। उनकी सिलाई से होने वाली आमदनी घर के खर्च में सहयोग देती है। वहीं महतारी वंदन योजना से मिलने वाली राशि बच्चों की पढ़ाई-लिखाई और अन्य जरूरी जरूरतों को पूरा करने में भी सहायक बन रही है। यशोदा का कहना है कि नियमित आर्थिक सहायता से महिलाओं को अपनी छोटी-बड़ी जरूरतों के लिए आर्थिक संबल मिलता है। इससे वे अपनी जरूरत के अनुसार राशि का उपयोग करने के साथ भविष्य के लिए बचत भी कर सकती हैं। हुनर और आर्थिक संबल से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम' यशोदा के लिए महतारी वंदन योजना की आर्थिक सहायता केवल मासिक सहयोग तक सीमित नहीं रही, बल्कि उनके हुनर को आगे बढ़ाने का माध्यम भी बनी। सिलाई के काम से होने वाली आय और योजना से मिली आर्थिक सहायता का समझदारी से उपयोग कर वे परिवार की आर्थिक मजबूती में योगदान दे रही हैं।

बहतराई एक्सीलेंस सेंटर में खिलाड़ियों की डाइट पर विभाग सख्त, 24 घंटे में मांगा जवाब

खराब भोजन की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई, भोजन प्रदायक फर्म और अधिकारी को नोटिस

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। बहतराई, बिलासपुर स्थित खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में खिलाड़ियों को दिए जा रहे भोजन की गुणवत्ता की शिकायत पर खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने तत्काल सज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। खिलाड़ियों के भोजन में लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए विभाग ने बिलासपुर में विभागीय सहायक संचालक तथा संबंधित भोजन प्रदायक फर्म को नोटिस जारी किया है। दोनों को 24 घंटे के भीतर

स्पष्टीकरण के साथ तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। खेल एवं युवा कल्याण विभाग की संचालक मती आकांक्षा शिक्षा खलखो ने खिलाड़ियों की डाइट के मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारी तथा भोजन प्रदायक फर्म से जवाब तलब किया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि मामले में सामने आए तथ्यों की वास्तविक स्थिति का परीक्षण किया जाएगा। विभाग ने तथ्यों की स्थल जांच और वस्तुस्थिति की पड़ताल के लिए

संचालनालय स्तर से दो खेल अधिकारियों की जांच समिति भी गठित की गई है। समिति बहतराई स्थित खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में मामले का परीक्षण करेगी और जांच के बाद तथ्यात्मक प्रतिवेदन संचालनालय को प्रस्तुत करेगी। इस जांच के आधार पर सामने आने वाली वस्तुस्थिति के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। खिलाड़ियों के भोजन, स्वास्थ्य और मूलभूत सुविधाओं में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।

अनुशासन, आत्मविश्वास और ऊर्जा के साथ लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है खेल - उप अरुण साव

रायपुर। उप मुख्यमंत्री अरुण साव आज चांपा के सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित विद्याभारती मध्यक्षेत्र क्षेत्रीय कबड्डी खेलकूद प्रतियोगिता-2026 के समापन समारोह में शामिल हुए। उन्होंने प्रतियोगिता में शामिल खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। समापन कार्यक्रम में विजेता टीम को मोमेन्टो, प्रशस्ति पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया गया। सांसद मती कमलेश जांगड़ भी समापन कार्यक्रम में शामिल हुईं।



उप मुख्यमंत्री अरुण साव आज चांपा में शामिल हुईं।

के सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित विद्याभारती मध्यक्षेत्र क्षेत्रीय कबड्डी खेलकूद प्रतियोगिता-2026 के समापन समारोह में शामिल हुए। उन्होंने प्रतियोगिता में शामिल खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। समापन कार्यक्रम में विजेता टीम को मोमेन्टो, प्रशस्ति पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया गया। सांसद मती कमलेश जांगड़ भी समापन कार्यक्रम में शामिल हुईं।

सेवा संकल्प अभियान के तहत नुकड़ नाटक और रंगोली से विद्यार्थियों ने दिया जागरूकता एवं राष्ट्र निर्माण का संदेश



मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत पेंड्रा में मल्टीपर्स स्कूल के सामने विद्यार्थियों द्वारा नुकड़ नाटक एवं रंगोली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डाइट के बालक-बालिकाओं ने प्रभावी अभिनय, संवाद और रचनात्मक प्रस्तुतियों के माध्यम से सेवा भाव, सामाजिक जिम्मेदारी, स्वच्छता, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और राष्ट्र निर्माण से जुड़े महत्वपूर्ण संदेश आमजन तक पहुंचाए। नुकड़ नाटक के माध्यम से विद्यार्थियों ने स्वास्थ्य, स्वच्छता, राष्ट्र और पर्यावरण संरक्षण जैसे विषयों को सहज एवं प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। विद्यार्थियों ने अपने अभिनय के माध्यम से स्वच्छ गांव और स्वस्थ समाज की अवधारणा को सामने रखते हुए नागरिकों से स्वच्छता अपनाने, पानी और बिजली की बचत करने तथा पर्यावरण संरक्षण के प्रति सजग रहने का आह्वान किया। प्रस्तुति में युवाओं की भूमिका पर भी विशेष जोर दिया गया। विद्यार्थियों ने आत्मनिर्भरता, स्वरोजगार और मेहनत एवं लगन के साथ आगे बढ़ने का संदेश देते हुए युवाओं से समाज और राष्ट्र की प्रगति में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि युवा केवल अपने भविष्य के निर्माण तक सीमित न रहकर सामाजिक बदलाव और राष्ट्र निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

एकता, भाईचारे और जिम्मेदार नागरिकता का संदेश: नुकड़ नाटक के दौरान एकता, भाईचारे और सामाजिक जिम्मेदारी के महत्व को भी रेखांकित किया गया। विद्यार्थियों ने अपने अभिनय के माध्यम से यह संदेश दिया कि समाज में सकारात्मक बदलाव केवल किसी एक व्यक्ति के प्रयास से नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की सक्रिय सहभागिता से संभव है। सेवा भाव और सामाजिक सरोकारों को जीवन का हिस्सा बनाने के लिए आमजन को प्रेरित किया गया।

रंगोली के रंगों से दिया जागरूकता का संदेश: कार्यक्रम में रंगोली भी आकर्षण का प्रमुख केंद्र रही। विद्यार्थियों ने रंगों और कलात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक सरोकारों और राष्ट्र निर्माण से जुड़े संदेशों को आकर्षक रूप में प्रस्तुत किया। रंगोली के माध्यम से विद्यार्थियों ने यह संदेश सहज और प्रभावी तरीके से आमजन तक पहुंचाया कि छोटे-छोटे प्रयासों से समाज में बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। विद्यार्थियों की उत्साहपूर्ण भागीदारी ने बढ़ाया आयोजन का प्रभाव पूरे आयोजन में विद्यार्थियों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखने को मिली। नुकड़ नाटक और रंगोली के माध्यम से विद्यार्थियों ने अपनी रचनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन करने के साथ सामाजिक विषयों के प्रति अपनी संवेदनशीलता भी प्रदर्शित की।

'सेवा की कहानी: आयुष्मान कार्ड से शिशु खलखो को इलाज के खर्च की चिंता से मिली राहत

'आयुष्मान कार्ड बना परिवार के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा का संबल, पांच लाख रुपये तक नि:शुल्क उपचार की सुविधा'

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। सेवा संकल्प अभियान के तहत शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से आम नागरिकों के जीवन में आ रहे बदलाव की कहानियां सामने आ रही हैं। सरगुजा जिले के बतौली विकासखंड की ग्राम पंचायत घोघरा निवासी मती शिशु खलखो के लिए आयुष्मान कार्ड स्वास्थ्य सुरक्षा के साथ आर्थिक राहत का भी माध्यम बना है। पहले परिवार में किसी सदस्य के बीमार होने पर उपचार के खर्च की चिंता उनके घरेलू बजट पर असर डालती थी। अब आयुष्मान कार्ड बनने से पात्रता एवं योजना के प्रावधानों के अनुसार पांच लाख रुपये तक नि:शुल्क उपचार की सुविधा का लाभ मिल सकेगा। मती शिशु खलखो ने बताया कि सुशासन तिहार के दौरान उनकी समस्या का समाधान हुआ और उनका आयुष्मान कार्ड बनाया गया। कार्ड मिलने के बाद बीमारी की स्थिति में उपचार पर होने वाले बड़े खर्च को लेकर उनकी चिंता पहले की तुलना में कम हुई है। सीमित आय वाले परिवार के लिए स्वास्थ्य संबंधी आकस्मिक खर्च कई बार घरेलू जरूरतों और बजट



को प्रभावित करता था, लेकिन आयुष्मान कार्ड ने उन्हें स्वास्थ्य सुरक्षा का भरोसा दिया है। 'इलाज के खर्च से मिली राहत, परिवार को मिला भरोसा' शिशु खलखो बताती हैं कि पहले परिवार में किसी के बीमार पड़ने पर इलाज के लिए बड़ी राशि जुटानी पड़ती थी। इससे घर के दूसरे जरूरी खर्च प्रभावित होते थे और आर्थिक स्थिति पर अतिरिक्त बोझ पड़ता था। अब आयुष्मान कार्ड उनके परिवार के लिए

उपचार के समय आर्थिक सहारा बन गया है। आयुष्मान कार्ड के माध्यम से पात्र हितग्राहियों को योजना के प्रावधानों के अनुसार उपचार की सुविधा मिलने से गंभीर बीमारी या आकस्मिक स्वास्थ्य जरूरत के समय परिवार पर पड़ने वाले आर्थिक दबाव को कम करने में मदद मिलती है। शिशु खलखो के लिए यह कार्ड बीमारी के समय इलाज की सुविधा के साथ आर्थिक सुरक्षा का भरोसा भी लेकर आया है।

'जनकल्याणकारी योजनाओं से मजबूत हो रहा सामाजिक सुरक्षा का आधार': सेवा संकल्प अभियान के माध्यम से शासन की योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों की कहानियां जन-जन तक पहुंचाई जा रही हैं। शिशु खलखो की कहानी बताती है कि जब जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंद और पात्र परिवारों तक पहुंचता है, तो स्वास्थ्य जैसी महत्वपूर्ण आवश्यकता के समय उन्हें उपचार के साथ आर्थिक सुरक्षा का भी संबल मिलता है।

भोरमदेव कॉरिडोर के निर्माण में तेजी लाने उप मुख्यमंत्री एवं पर्यटन मंत्री के कड़े निर्देश

निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति पर उप मुख्यमंत्री एवं पर्यटन मंत्री ने ठेकेदारों और निर्माण एजेंसियों के प्रति जताई नाराजगी

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। स्वदेश दर्शन योजना के तहत लगभग 146 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किए जा रहे भोरमदेव कॉरिडोर के सभी प्रोजेक्ट की प्रगति की आज उप मुख्यमंत्री एवं कर्वाय विभागक विजय शर्मा और पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने कबीरधाम के जिला पंचायत सभाकक्ष में समीक्षा की। समीक्षा के दौरान कई निर्माण कार्य अपेक्षा के अनुरूप गति से नहीं चलने पर दोनों मंत्रियों ने संबंधित ठेकेदारों और निर्माण एजेंसियों के प्रति कड़े नाराजगी जताई। उन्होंने हर 15 दिन के लिए स्पष्ट कार्ययोजना तैयार कर निर्माण कार्यों में तेजी लाने और निर्धारित समय-सीमा में ठेस प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि भोरमदेव कॉरिडोर के निर्माण कार्यों में अपेक्षित गति नहीं होने पर अब जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि हर 15 दिन में कार्य की प्रगति निर्माण स्थल पर दिखाई देनी चाहिए। निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप प्रगति नहीं होने पर जिम्मेदार ठेकेदारों को कार्य से पृथक करने के साथ अनुबंध की शर्तों के तहत कड़े कार्रवाई की जाएगी। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि भोरमदेव कॉरिडोर का निर्माण महत्वपूर्ण और दीर्घकालिक परियोजना है। ठेकेदार एजेंसियों की लापरवाही किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। जिन कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं होगी, वहां संबंधित ठेकेदार को कार्य से पृथक कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर अनुबंध की



शर्तों के तहत ब्लैक लिस्ट सहित अन्य कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने सभी प्रोजेक्ट के लिए 15-15 दिन की स्पष्ट कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि कार्ययोजना केवल कामगजों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि निर्धारित अवधि के बाद निर्माण स्थल पर उसका परिणाम स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। पर्याप्त मशीनरी, मानव

संसाधन और आवश्यक संसाधन उपलब्ध करार निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि भोरमदेव क्षेत्र का विकास आने वाले कई वर्षों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। इसलिए प्रत्येक निर्माण कार्य मजबूत, टिकाऊ और निर्धारित गुणवत्ता एवं तकनीकी मानकों के अनुरूप होना चाहिए। निर्माण की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का

समझौता नहीं किया जाएगा। कार्यों में किसी तरह की तकनीकी अथवा अन्य समस्या आने पर संबंधित अधिकारियों को तत्काल इसकी जानकारी दे दें, ताकि समय रहते उसका समाधान किया जा सके। इसलिए सभी संबंधित एजेंसियां पूरी गंभीरता और आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। आगामी भोरमदेव महोत्सव तक निर्माण कार्यों में स्पष्ट और दिखाई देने वाली प्रगति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने पीएमसी, ठेकेदारों और भोरमदेव विकास समिति के बीच निरंतर समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए। साथ ही पीएमसी की भूमिका एवं जिम्मेदारियों की समीक्षा कर तकनीकी निगरानी को और प्रभावी बनाने को कहा। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने भी भोरमदेव कॉरिडोर के निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति पर कड़े नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि कई कार्यों के कार्यदिश जारी हुए 8 से 09 माह हो चुके हैं, इसके बावजूद निर्माण कार्य अपेक्षा के अनुरूप गति से नहीं चल रहे हैं। मंत्री अग्रवाल ने सभी ठेकेदारों को पूर्ण कार्ययोजना प्रस्तुत करने तथा प्रत्येक 15 दिन में किए जाने वाले कार्यों का लक्ष्य निर्धारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भोरमदेव महोत्सव से 10 दिन पहले तक निर्धारित कार्यों को पूरा करने की समय-सीमा तय की जाए। प्रत्येक 15 दिन में कार्यों की प्रगति की समीक्षा होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य नहीं करने वाले ठेकेदार को कार्य से पृथक करने तथा अनुबंध की शर्तों के अनुसार कड़े कार्रवाई की जाएगी।